● वर्ष-5

● अंक-231

रायपुर, शुक्रवार
15 मई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› सुशासन तिहार: जन-विश्वास का...

भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बनाएगा समावेशी विश्व व्यवस्था

ग्लोबल साउथ को मिलेगा नया मंच: मोदी

नईदिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों का समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और अधिक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में मिलकर काम करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स आज उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है और यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आवाज देने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स संगठन आर्थिक मजबूती बढ़ाने, वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और संतुलित विश्व व्यवस्था तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाएगा।

ग्लोबल साउथ को मजबूत करने पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में विकासशील देशों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखने की आवश्यकता है। ब्रिक्स इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में बहुपक्षवाद यानी मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत करना समय की जरूरत है। भारत चाहता है कि सभी देशों को समान अवसर मिले और वैश्विक संस्थाओं में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले पीएम मोदी

ब्रिक्स बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। बैठक के दौरान लावरोव ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की जानकारी भी दी। यह प्रगति दिसंबर 2025 में आयोजित 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद हुई पहलों से जुड़ी बताई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने रूस के साथ विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दो दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में शुरू हुई। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर कर रहे हैं। इस उच्चस्तरीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और कई साझेदार देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आर्थिक सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में होगा एसआईआर

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चरण-3 को 16 राज्यों और 03 केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया है।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि एसआईआर के चरण-3 को 16 राज्यों और 03 केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम जनगणना के तहत चल रही घर-घर सूचीकरण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आयोग ने बताया कि चरण-3 के तहत हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे देश को कवर किया जाएगा। इन क्षेत्रों में मौसम और हिमपात की स्थिति को देखते हुए बाद में कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।इस अभियान के दौरान 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करेंगे। उनके सहयोग के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी तैनात रहेंगे।

आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलए नियुक्त करने की अपील की है, ताकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सहभागिता के साथ संपन्न हो सके।

आयोग ने कहा कि पहले दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया था, जहां 6.3 लाख से अधिक बीएलओ और 9.2 लाख बीएलए विभिन्न चरणों में शामिल रहे। चरण-3 के कार्यक्रम के अनुसार ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन पांच जुलाई को होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 06 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय सहित कई राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 07 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बाद में होगा

आयोग ने बताया कि एसआईआर का तीसरा चरण पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश इसमें कवर हो जाएगा। आयोग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मतदाता सूची के कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी, जिसमें बर्फ से ढके क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि, मतदाता सूची के तीसरे चरण में दिल्ली को शामिल किया जाएगा, जहां 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

केंद्र शासित प्रदेश में हुआ

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर का दूसरा चरण नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2205 से किया गया था।

रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज रायपुर जिले के सेरीखेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत संचालित इस केंद्र में उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और आजीविका गतिविधियों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित अजा परियोजना और बेहतर बाजार लिंकेज की प्रशंसा करते हुए इसे देशभर के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया।

शांति की भाषा पर संघ के साथ दिखे पूर्व सेना प्रमुख

पाकिस्तान के साथ बातचीत पर दिया जोर

मुंबई,। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान के साथ भविष्य के संबंधों और संवाद को लेकर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान का पुरजोर समर्थन किया है, जिसमें पाकिस्तान के साथ बातचीत और जन-संपर्क (पीपुल-टू-पीपुल कॉन्टैक्ट) को महत्व देने की बात कही गई थी। पूर्व सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए नागरिकों के बीच आपसी संवाद एक प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है।

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनरल नरवणे ने कहा कि सीमा के दोनों ओर रहने वाले आम लोगों की बुनियादी समस्याएं—रोटी, कपड़ा और मकान—एक जैसी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति से दूर, जब दोनों देशों के आम नागरिकों के बीच मित्रता और विश्वास का भाव पैदा होगा, तभी दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रैक-टू कूटनीति यानी अनौपचारिक बातचीत और खेल आयोजनों जैसे माध्यमों से लोगों के बीच जुड़ाव होना चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख के अनुसार, हमारे नागरिकों को यह समझना आवश्यक है कि सीमा पार रहने वाला हर व्यक्ति कट्टर दुश्मन नहीं होता।

हालांकि, शांति और संवाद की वकालत करने के साथ-साथ जनरल नरवणे ने भारत की सैन्य दृढ़ता को लेकर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बातचीत की इच्छा रखने का अर्थ यह कतई नहीं है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। उनके शब्दों में, भारत हमेशा शांति की भाषा बोलने वाला देश रहा है, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो हम जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। यह बयान दत्तात्रेय होसबोले के उस हालिया बयान की निरंतरता में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने भारत का भरोसा खो दिया है, इसलिए अब वहां के नागरिक समाज और आम लोगों को संवाद की कमान संभालनी चाहिए। जनरल नरवणे और संघ के नेता की इस जुगलबंदी ने रक्षा और कूटनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या भारत अब पाकिस्तान के साथ नागरिक कूटनीति के जरिए नए रास्ते तलाशने की तैयारी में है।

प्रमुख समाचार

वी.डी. सतीशान होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री

तिरुवनंतपुरम। कई दिनों की परामर्श और बढ़ते सस्पेंस के बाद, कांग्रेस ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशान को केरल का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। यह निर्णय नई दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बीच गहन चर्चा के बाद लिया गया, जिसमें पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए दावे किए जा रहे थे। सतीशान की पदोन्नति से उस लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता का अंत हो गया है जिसने केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की शानदार जीत पर ग्रहण लगा रखा था, जहां गठबंधन ने 140 में से 102 सीटें हासिल की थीं। तिरुवनंतपुरम स्थित केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) मुख्यालय में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सतीशान को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना गया। जिससे उनके लिए अगली सरकार बनाने का दावा पेश करने का रास्ता खुल गया।

हिमंता की पत्नी पर आरोपों के बाद गुवाहाटी पहुंचे पवन खेड़ा

गुवाहाटी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ लगे आरोपों से जुड़े एक मामले में गुवाहाटी पुलिस के सामने पेश हुए। खेड़ा जांच में सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गुरुवार को गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन पर हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा से जुड़े पासपोर्ट विवाद का आरोप है। पुलिस स्टेशन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और मैं इसमें सहयोग कर रहा हूं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी, रिनिकी भुयान शर्मा के पास भारत, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं और दुबई में उनकी कुछ संपत्तियां अज्ञात हैं, साथ ही अमेरिका के व्योमिंग में उनकी एक कंपनी भी है। शर्मा परिवार ने इन दावों का पुरजोर खंडन करते हुए पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों द्वारा प्रसारित दस्तावेजों को एआई द्वारा निर्मित मनगढ़ंत कहानियां बताया है।

वकील की ड्रेस पहनकर ममता कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को काले रंग के वकील के गाउन में कलकत्ता उच्च न्यायालय में पेश हुईं। यह मामला विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की करारी हार के बाद राज्य में हुई हिंसा से संबंधित है। वरिष्ठ टीएमसी नेता और अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय के पुत्र शिरशन्या बंदोपाध्याय द्वारा दायर यह मामला राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालयों पर हुए हमलों से संबंधित है। ये हमले उन महत्वपूर्ण चुनावों के बाद हुए थे, जिन्होंने पार्टी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया और भाजपा को राज्य में सत्ता में लाया। एक्स पर एक पोस्ट में टीएमसी ने कहा कि आज अदालत में उनकी शारीरिक उपस्थिति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और कहा कि वह बंगाल के लोगों को उनकी जरूरत के समय कभी नहीं छोड़ती हैं और सत्य, न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए अपनी लड़ाई में प्रतिबद्ध हैं।इसमें आगे कहा गया है कि वह लगातार नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर करुणा, साहस और दृढ़ विश्वास का प्रदर्शन करती हैं।

भाजपा विधायक रथींद्र बोस विस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित विधायक रथींद्र बोस को पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बोस कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रथींद्र बोस को पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। अधिकारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रथींद्र बोस की उम्मीदवारी को सभी दलों का समर्थन मिलेगा और उन्हें सर्वसम्मति से चुना जाएगा। भाजपा के रथींद्र बोस ने कूच बिहार दक्षिण सीट से भाजपा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। बोस ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) उम्मीदवार अविजित डे भौमिक को पटखनी दी और 23,284 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 108,482 वोट मिले। वहीं, टीएमसी उम्मीदवार को 85,198 वोट मिले थे। इस सीट पर 23 दौर की मतगणना चली।

डीएमके गठबंधन कमजोर नहीं हुआ : एमके स्टालिन

चेन्नई। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव भले ही जीत नहीं मिली है, लेकिन डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा 1.54 करोड़ वोट हासिल करने की क्षमता तमिलनाडु की जनता के गठबंधन पर रखे गए भरोसे को दर्शाती है। चुनाव परिणामों के बाद अधिकांश सहयोगी दलों ने खुले तौर पर कहा है कि वे अपनी गठबंधन बदले बिना डीएमके के साथ ही अपना राजनीतिक सफर जारी रखेंगे। स्टालिन ने कहा, यह डीएमके के प्रति सहयोगी दलों के नेताओं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां एक बयान में कहा इसी के अनुरूप, हम सिद्धांतवादी राजनीतिक दलों के रूप में एकजुट होकर जनता के कल्याण और राज्य के गठन के लिए हमेशा की तरह अपना सफर जारी रखेंगे। तमिलनाडु की रक्षा करने की शक्ति और जुझारूपन हमारे भीतर ही है।

सोना खरीदने से मना करने के देशहित कारण

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका ईरान तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही तेजी, रुपये पर बढ़ता दबाव और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर गहराती चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बचत करने की अपील की है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचने, विदेश यात्राएं टालने और जहां संभव हो वहां घर से काम करने जैसे उपाय अपनाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है और होरमुज जलडमरूमध्य में बाधा आने से तेल की आपूर्ति को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया है। हम आपको बता दें कि यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में गिना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतें एक सौ पांच डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रुपये में कमजोरी आई है और आयात बिल लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान देश ने घर से काम, वर्चुअल बैठकों और वीडियो संवाद जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया था। अब समय आ गया है कि इन तरीकों को फिर से व्यापक रूप से अपनाया जाए ताकि ईंधन की खपत कम हो और विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।

उन्होंने लोगों से मेट्रो रेल का अधिक उपयोग करने, कार पूल जैसी

शेयरिंग व्यवस्था अपनाने और बिजली से चलने वाले वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील की। साथ ही माल परिवहन को सड़कों की बजाय रेलमार्ग की ओर ले जाने की बात भी कही ताकि डीजल पर निर्भरता घटाई जा सके। हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया संकट के बाद भारत का ईंधन आयात खर्च तेजी से बढ़ा है और यदि होरमुज जलडमरूमध्य में बाधा लंबे समय तक बनी रही तो तेल की ऊंची कीमतें कई महीनों तक बनी रह सकती हैं।

प्रधानमंत्री की सबसे अधिक चर्चा में रही अपील सोने की खरीद को लेकर थी। उन्होंने कहा कि देशहित में नागरिकों को कम से कम एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचना चाहिए। हम आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में शामिल है और विवाह तथा त्योहारों के मौसम में इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है। चूंकि सोना मुख्य रूप से विदेशों से आयात किया जाता है, इसलिए इसकी अधिक खरीद से डॉलर बाहर भेजना पड़ता है और भारत के घरेलू विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत के लिए कच्चे तेल और सोने में एक समानता है। दोनों का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदा जाता है और भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। जब तेल महंगा होता है और साथ ही सोने की मांग भी बढ़ जाती है, तब देश को आयात के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे चालू खाते का घाटा बढ़ता है और रुपये पर दबाव आता है। यही कारण है कि आर्थिक संकट के समय सरकारें अक्सर सोने के आयात को नियंत्रित करने के उपाय करती रही हैं। अतीत में भी आयात शुल्क बढ़ाने, आयात पर रोक लगाने और वैकल्पिक योजनाओं को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने लोगों से अनावश्यक विदेश यात्राएं, विदेशी पर्यटन और विदेशों में आयोजित होने वाले विवाह समारोह भी एक वर्ष तक टालने का आग्रह किया। उनका कहना था कि मध्यम वर्ग में विदेश घूमने और विदेश में विवाह करने का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन मौजूदा वैश्विक संकट के समय विदेशी मुद्रा बचाना राष्ट्रीय आवश्यकता बन गया है।

इस बीच, अमेरिका ईरान युद्ध का असर वैश्विक सोना बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।

बस्तर में बदलेगी सुरक्षा कैंप की तस्वीर

■ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनेंगे जन सुविधा केंद्र, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे नई शुरुआत

जगदलपुर। बस्तर एक ऐसा इलाका जो कभी नक्सलवाद की पहचान से जाना जाता था पर अब उसी बस्तर की तस्वीर तेजी से बदल रही है, जहां पहले सुरक्षा कैंप सिर्फ ऑपरेशन का केंद्र हुआ करते थे, अब वही कैंप विकास और जनसेवा के केंद्र बनते नजर आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की नई रणनीति के तहत फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी सुरक्षा कैंप अब स्थानीय लोगों और सुरक्षाबलों के बीच सेतु का काम करेंगे। इस बदलाव की शुरुआत खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह नेतनार सीआरपीएफ कैंप से करने जा रहे हैं। बस्तर संभाग के सभी सुरक्षा कैंप अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इन कैंपों के 3 से 4 बैरकों में जन समस्या निवारण और जनसुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में ग्रामीणों को डिजिटल सेवा केंद्र की सुविधा मिलेगी, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चलाई जाएगी और जंगल आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग भी यहीं होगी। यानि एक ही कैंप में जवान भी तैनात रहेंगे और विकास की गतिविधियां भी समानांतर चलेंगी।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने सुरक्षा काफिल में शामिल गाडियों की संख्या किया कम

बिलासपुर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने सुरक्षा काफिले, फॉलो वाहन और आधिकारिक कन्वॉय में शामिल गाडियों की संख्या कम करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी और संसाधनों के संतुलित उपयोग की सोच से प्रेरित होकर लिया है। साहू ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए संसाधनों का जिम्मेदार और संतुलित उपयोग समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर देशवासियों को सादगी, ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में सादगी, ऊर्जा संरक्षण, आत्मनिर्भरता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को केवल सरकारी पहल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक जनआंदोलन बनाया जाना चाहिए। साहू ने लोगों से भी अपील की कि वे दैनिक जीवन में छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर ऊर्जा और संसाधनों की बचत में योगदान दें। उनका मानना है कि सामूहिक प्रयासों से ही देश आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है।

खाट पर मिले चारों शव, दादा-दादी और नाती-नातिन की हत्या

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के भावतरा गांव में पारिवारिक विवाद और जमीन संबंधी मामले को लेकर चार लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में 70 वर्षीय मेदनी प्रसाद कश्यप, उनकी पत्नी कांति बाई, 17 वर्षीय नाती पीतांबर और नतनीन मोगरा शामिल हैं।

जिले के गांव भावतरा में बीती रात पारिवारिक विवाद और जमीन संबंधी मामले को लेकर चार लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के संदेही सोनसाय और उसके बेटे गोलू को हिरासत में लिया है। सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल भेजे गए हैं।

ग्राम भावतरा निवासी मेदनी प्रसाद कश्यप (70 वर्ष), उनकी पत्नी कांति बाई, नाती पीतांबर (17 वर्ष) और नतनी मोगरा (मुख बाधित) बुधवार रात करीब 9 बजे खाना खाकर सो गए थे। पीछे नया मकान बन रहा था। सुबह लगभग 7:30 बजे जब एक परिजन घर पहुंचा, तो सामने का दरवाजा बंद मिला। उसने पीछे से जाकर देखा तो चारों खाट पर मृत अवस्था में पड़े थे। इसके बाद घटना की सूचना सरपंच के माध्यम से तत्काल पुलिस को दी गई।

पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप सहित पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर को सील कर दिया। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और श्वान दल की टीम भी मौके पर पहुंची। श्वान दल ने जांच के दौरान घर के पीछे बाड़ी के रास्ते संदेही सोनसाय के घर का पता लगाया। संदेही के घर पर ताला लगा था, जिसे तोड़ने पर हत्या में प्रयुक्त टांगी बरामद की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि यह मामला पारिवारिक विवाद और जमीन से जुड़ा हुआ है। चारों शव खाट पर थे, जिनमें दादी और मोगरा एक खाट पर सो रहे थे, जबकि दादा और नाती दूसरी खाट पर मृत पाए गए। पुलिस ने सभी आवश्यक सबूत एकत्रित कर आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू की है।

संदेही सोनसाय कश्यप का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसने 17 साल पहले अपने छोटे भाई की भी निर्मम हत्या की थी, जिसके लिए वह जेल जा चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है।

बिलासपुर में 13 पेट्रोल-पंप सूखे, कुछ में लगा नो स्टॉक के बोर्ड

बिलासपुर। शहर और आउटर के करीब 13 पेट्रोल पंप पूरी तरह सूख चुके हैं और दूसरी ओर कई पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड लग गए है। इसका ज्यादा असर एचपीसीएल के पंपों पर है, जबकि बीपीसीएल के पंप में डीजल-पेट्रोल की कमी हो गई है। आईओसीएल के कुछ पंप ड्राई हुए हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षाकृत जल्दी सप्लाई मिल जा रही है। शहर के प्रमुख पेट्रोल पंप के साथ ही जिले के पेट्रोल पंप में भी इन दिनों पेट्रोल-डीजल संकट गहराता नजर आ रहा है और लोगों को पेट्रोल पंपों के चक्कर काटने पड रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जिन पंपों में पेट्रोल-डीजल बचा है, वहां भी कटौती शुरू हो गई है। लोग अब सामान्य से ज्यादा पेट्रोल डलवा रहे हैं। कई जगह वाहन चालकों की लाइन लग रही है। हालांकि, प्रशासन का दावा है कि जिले में पांच दिन का स्टॉक मौजूद है । टैगोर चौक, पुलिस पेट्रोल पंप, सीपत चौक और बैमा-नगोई चौक के पंपों पर सामान्य दिनों से ज्यादा भीड़ दिखी। कर्मचारियों का कहना है कि लोग पहले से ज्यादा पेट्रोल मांग रहे हैं। कई वाहन चालक साफ कह रहे हैं कि अगर बाकी पंप भी बंद हो गए तो परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए पहले से टंकी फुल करवा रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों के पंप संचालकों ने अपने स्तर पर बिक्री सीमित कर दी है। बाइक चालकों को 500 की जगह 200 रुपए तक का पेट्रोल दिया जा रहा है। कार वालों को 1000 रुपए और बड़े वाहनों को सीमित डीजल मिल रहा है। संचालकों का कहना है कि एडवांस पेमेंट के बाद भी सप्लाई दो से तीन दिन की देरी से मिल रही है। पंप संचालकों के मुताबिक एचपीसीएल के पंपों में सबसे ज्यादा दिक्कत है। बीपीसीएल के पंप भी प्रभावित हैं। कुछ तेल कंपनियों ने हालात को देखते हुए सप्लाई नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। कई पंपों पर एक बार में सीमित मात्रा में ही ईंधन देने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं 40 लीटर तो कहीं 50 लीटर तक की सीमा तय की गई है। इसका उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और अधिक से अधिक लोगों तक ईंधन पहुंचाना है। हालांकि, इस व्यवस्था से बड़े वाहन संचालकों और ट्रांसपोर्टरों की परेशानी बढ़ गई है। फूड कंट्रोलर अमृत कुजूर ने दावा किया है शहर के 9 पंप संचालकों का पेमेंट हो चुका है और उन्हें जल्द सप्लाई मिल जाएगी। चार सर्विस स्टेशनों का भुगतान लंबित है। ऑयल कंपनियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और एक-दो दिन में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। वहीं, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि जिले में बड़ी शॉर्टेज नहीं है और तेल कंपनियों के माध्यम से सप्लाई बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। इधर, पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष नवदीप सिंह अरोरा का कहना है कि कुछ पेट्रोल पंप ड्राई होने की सूचना मिली है लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं है। शहर का गंगा फ्यूल्स पहले से बंद है, जबकि नेहरू चौक का पंप तीन बार ड्राई हो चुका है। देवकीनंदन चौक का पंप भी एक माह से बंद है। बुधवार को आउटर के कई पंपों में अचानक पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया। कुछ पंप तीन दिन से सूखे पड़े हैं।

नारसापुर के फड़ मुंशी ने 70 परिवारों को तेंदूपत्ता तोडने नहीं दिया

बीजापुर। जिले के उसूर विकासखंड अंतर्गत नारसापुर गांव के फड़ मुंशी की लापरवाही के कारण लगभग 70 परिवारों को तेंदूपत्ता तोडने नहीं दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि फड़ मुंशी ने अधिक काम होने तथा अपने ट्रैक्टर को रेती और मिट्टी ढुलाई जैसे निजी कार्यों में लगाए रखने का हवाला देकर पत्ता तुड़ाई बंद करा दी। इसके चलते बड़ी मात्रा में पत्ता जंगल में ही खराब होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि दो वर्षों बाद जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण शुरू होने से उनके चेहरे पर खुशी लौटी थी और उन्हें रोजगार व अतिरिक्त आय की उम्मीद जगी थी, लेकिन प्रबंधक एवं फड़ मुंशी की लापरवाही ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पत्ता नहीं टूटने से कई परिवारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नारसापुर के ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर तेंदूपत्ता तुड़ाई शुरू कराने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को रोजगार और उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सके।

प्यार में युवती के पिता पर चलाई गोली, फरार आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। बालको थाना क्षेत्र में युवती के पिता पर गोली चलाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना में फरार चल रहे शातिर आरोपी को बालको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ डकैती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। मामला 19 फरवरी का है, जब बालको थाना इलाके के दोन्द्रों संगम नगर में प्रेम प्रसंग को लेकर युवती के पिता पर गोली चलाई गई थी। गनीमत रही कि गोली युवक के पिता को नहीं लगी और वे बाल-बाल बच गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बालको निवासी 22 वर्षीय साहिल मासी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए थे, लेकिन वारदात की साजिश रचने और देशी कट्टा उपलब्ध कराने वाला आरोपी लगातार फरार चल रहा था। बालको थाना प्रभारी ने टीम के साथ इलाके में घेराबंदी कर मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी को दबोच लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले में जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

सुशासन तिहार में हंगामे के बाद पार्षद प्रीति समुंद्रे समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज

राजनांदगांव। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार-2026 के दौरान विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने पार्षद प्रीति चमन समुंद्रे सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। मामला डोंगरगढ़ के अंबेडकर सांस्कृतिक भवन इंदिरा नगर का है, जहां शिविर के दौरान कथित रूप से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, अधिकारियों-कर्मचारियों को भवन के अंदर बंद करने और बिजली कनेक्शन काटने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार 13 मई 2026 को आयोजित सुशासन तिहार शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरानम काम में बाधा डालने की शिकायत नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक महेंद्र करसे ने दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि पट्टा वितरण की मांग को लेकर वार्ड पार्षद प्रीति चमन समुंद्रे अपने समर्थकों के साथ शिविर स्थल पहुंचीं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों को सांस्कृतिक भवन के भीतर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया गया। इतना ही नहीं, शिविर स्थल का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया, जिससे कार्यक्रम बाधित हो गया। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी और अन्य दस्तावेजों को भी प्रभावित किया गया। डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127(2), 221, 324(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भांजे ने महिला को ईंट, मुक्के श डंडे से पीटा, जेवर भी लूटे

कोरबा। सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र के काशीनगर खपराभट्ठा में एक महिला के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई है। महिला के भांजे और उसकी मां पर सोने के जेवर लूटने का आरोप लगा है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पीड़िता लालती देवी दिहोलिया (38 वर्ष) सिलाई का काम करती हैं। 13 मई 2026 को सुबह करीब 8:30 से 9:30 बजे वह अपनी बहन मनीषा ब्यास के घर गई थीं। वहां उनकी बड़ी बहन का लड़का अभिजीत गिरी उर्फ बाबूमणी और उसकी मां लीलावती गिरी भी पहुंच गए। दोनों ने बेवजह गाली-गलौज शुरू कर दी। मना करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ, मुक्के और डंडे से मारपीट की। अभिजीत ने लालती के दोनों हाथ, पैर, घुटना और चेहरे पर वार किया। उसने लालती के बाल खींचकर उसे घसीटा भी। आरोपियों ने बहन मनीषा के माथा, कान और गले पर भी चोट पहुंचाई। मारपीट के दौरान अभिजीत ने लालती देवी के कान में पहनी सोने की बाली और गले में पहनी सोने की मराठी माला लूट ली।

बिजली के खंभे पर तार धू-धू कर जले, दमकल विभाग ने पाया काबू

कोरबा। हाल ही में शहर के आरती नगर रेलवे लाइन के पास एक विद्युत खंभे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते खंभा और उसमें बंधे तार धू-धू कर जलने लगे। आग की लपटें उठती देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल वाहन और विद्युत विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिए विद्युत प्रवाह बंद किया गया। विभागीय कर्मियों और दमकल की मदद से आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग आसपास के मकानों तक नहीं पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खंभे पर तारों का मकड़जाल फैला हुआ था। केबल, इंटरनेट और बिजली के तार बेतरतीब तरीके से बंधे थे। इसी के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और खंभे ने आग पकड़ ली। आग लगने से तार जलकर टूट गए और सड़क पर गिर गए। आग लगने के बाद सुरक्षा कारणों से आसपास के क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था बंद कर दी गई। विद्युत विभाग ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया।

कलेक्टर जांगड़े ने चिरमिरी एवं खड़गवां क्षेत्र का व्यापक दौरा

एमसीबी। कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने विगत दिवस चिरमिरी एवं खड़गवां क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों, संस्थानों एवं ग्राम पंचायतों का व्यापक दौरा कर विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं तथा जनसुविधाओं की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। दौरे की शुरुआत कलेक्टर द्वारा चिरमिरी स्थित मंगल भवन के निरीक्षण से हुई। यहां उन्होंने भवन में आयोजित होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों की जानकारी लेते हुए उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान साउंड सिस्टम की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने उसे शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए, ताकि आगामी आयोजनों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके पश्चात कलेक्टर महोदया ने लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, चिरमिरी का निरीक्षण किया।

सरपंचों ने किया समाधान शिविर का बहिष्कार

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इस बीच गरियाबंद जिले में इसका बहिष्कार कर दिया गया है। अमलीपदर तहसील क्षेत्र में आने वाले 16 पंचायत के सरपंच लामबंद होकर आज झरगांव में आयोजित शिविर का बहिष्कार कर तहसीलदार गेंद लाल साहू को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। ज्ञापन में सरपंचों ने लिखा है कि 7 मई को अमलीपदर में आयोजित शिविर में भोजन का प्रबंध पंचायतों ने मिलकर किया था, लेकिन सरपंच खाना खाने बैठे तो उन्हें तहसीलदार गेंदलाल साहू द्वारा उठा दिया गया। नाराज सरपंचों ने अब इसे सभी सरपंच का अपमान बताकर तहसीलदार को हटाने की मांग रख दिया। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दिया है। इसी बीच तहसीलदार गेंद लाल साहू ने भरे मंच में सफाई देते हुए पहचान नहीं होने से भूल होने की बात कहकर माफी मांगकर मामले को शांत करने को कोशिश किया।

कोयला लदी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग

बिलासपुर। जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कोयला से भरी एक मालगाड़ी के वैगन में अचानक धुआं उठ उसमें से आग लग गई। घटना गतौरा रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। लेकिन इलाके में किसी भी प्रकार के जन हानि की पुष्टि नही की है। आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और दमकल विभाग में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी बिलासपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान एक वैगन से धुआं और आग की लपटें निकलती दिखाई दीं, जिसके बाद तत्काल ट्रेन को गतौरा स्टेशन के पास रोका गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण कोयले में आग लगी हो सकती है। हालांकि रेलवे प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। घटना के चलते कुछ समय तक रेल परिचालन भी प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है।फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है।

वरिष्ठ भाजपा नेता व अपैक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष महावीर सिंह राठौड़ का निधन

कांकेर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व व अपैक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष महावीर सिंह राठौड़ का बुधवार की देर रात निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पूर्व मुख्यमंत्री व छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा. रमन सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महावीर सिंह राठौड़ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राठौड़ ने अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा संगठन और समाज सेवा के लिए समर्पित भाव से काम किया। उनका सरल, सहज और कर्मठ व्यक्तित्व हमेशा लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेगा। अपने शोक संदेश में कहा कि महावीर सिंह राठौड़ का निधन न सिर्फ भाजपा, बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने भगवान श्रीराम से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक जीवन से अलग उनका महावीर सिंह राठौड़ से आत्मीय संबंध था।

साप्ताहिक मिलन हिंदू समाज को संगठित करने का प्रमुख केंद्रः नाग

जगदलपुर। बजरंग दल के प्रांत संयोजक शुभम नाग का गुरूवार को एक दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर स्थित सीताराम शिवालय में एक बैठक आहूत की गई थी। बैठक की शुरुवात संघठन के पद्धति के अनुसार दीप प्रज्वलित कर ब्रह्मनाद एवं विजय महामंत्र के पश्चात शुभम नाग ने कार्यकर्ताओं को अपने उद्बोधन में युवाओं को संगठन से जुड़कर राष्ट्र एवं धर्म सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होने कहा कि बजरंग दल की ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा, संस्कार है, जिस पर बजरंग दल पर कार्य करता है। बजरंग दल हिंदू समाज की अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा उन्होंने विशेष रूप से साप्ताहिक मिलन केंद्र को और मजबूती से करने को कहा क्यों कि साप्ताहिक मिलन हिंदू समाज को संगठित करने का प्रमुख केंद्र है, इससे मठ मन्दिरों की सुरक्षा भी होगी। प्रांत संयोजक शुभम नाग ने कहा कि बस्तर में हो रहे अवैध कफन दफन के मामले आए दिन देखने को मिलते है ईसाई मिशनरी जानबूझकर गांव का माहौल खराब करने में कार्य करता है, और कई बार कांकेर आमाबेड़ा, नारायणपुर जैसे अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहते है। जिससे प्रदेश का छवि धूमिल होती है। बस्तर क्षेत्र माता दंतेश्वरी माता मावली की पवित्र भूमि है, जिसमें भगवान राम ने वनवास काल में अपनी वनवास काल अधिकता समय यही पर काटी बस्तर देवी देवताओं की भूमि है यहां के लोग माटी को अपनी मां मानते है, मां के साथ कोई खिलवाड़ करे बर्दास्त योग्य नहीं है।सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए मिशनरी अपने हरकतों से बाज आ जाए अन्यथा भोगने के लिए तैयार रहे। बैठक के दौरान संघठन की आगामी कार्य योजना एवं गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा कर रायपुर में होने वाले बजरंग दल प्रशिक्षण वर्ग में सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण लेने का आग्रह किया। विभाग संयोजक सिकंदर कश्यप ने बस्तर में हो रहे अवैध धर्मांतरण का पुरजोर विरोध करके कहा कि बजरंग दल अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है हमारे आदिवासी समाज को गुमराह करना बंद करे। जिला बस्तर शंकर लाल गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं को धर्म विरोधी तत्व जैसे लोगों को निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहने को कहा।

शराब दुकान बंद करने तीन गांव के ग्रामीण बैठे धरने पर

राजनांदगांव। गेंदाटोला स्थित शराब दुकान को बंद करने की मांग लेकर लुलीकसा, लोनाटोला और कोयलारी के ग्रामीण गुरुवार को धरने पर बैठ गए। हालांकि शराब दुकान के मुद्दे को लेकर गैंदाटोला के लोग समर्थन में है।

बताया जा रहा है कि प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गैंदाटोला में शराब दुकान बंद कराने को लेकर ग्रामीणों के बीच मतभेद उभरे हैं। तीन गांव के लोगों ने शराब दुकान बंद कराने के लिए सीधे प्रशासन से मांग की है। आवाज उठाने वाले लुलीकसा, लोनाटोला और कोयलारी के ग्रामीण शराब दुकान के संचालन से गांव में माहौल खराब होने की शिकायत कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से पंजाब के राज्यपाल श्री कटारिया ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से गुरुवार को लोकभवन में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान किया और श्री कटारिया ने भी श्री डेका को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा लोकभवन परिवार के साथ सामूहिक फोटोग्राफी भी कराई।

जनगणना की ड्यूटी निभाते हुए घायल हुई शिक्षिका

रायपुर। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में

मकान सूचिकरण कार्य के दौरान रायपुर की एक शिक्षिका हादसे का शिकार हो गईं। शासकीय स्कूल माना में पदस्थ शिक्षिका एवं जनगणना प्रगणक श्रीमती माधुरी विश्वास ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद श्रीमती विश्वास को एमएमआई नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर डॉ. सिंह आज स्वयं अस्पताल पहुंचे और श्रीमती विश्वास से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टरों के अनुसार वर्तमान में श्रीमती विश्वास की स्थिति स्थिर और सामान्य है।इस दौरान अपर कलेक्टर श्री मनीष मिश्रा भी उपस्थित रहे।

अनुदान पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और रोटावेटर जैसे कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आज से

रायपुर। अनुदान पर कृषि यंत्रों एवं सिंचाई पंपों (जैसे- डीजल/विद्युत पंप, ड्रिप सिस्टम) के लिए किसान चेम्प्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज़ (खसरा/बी-1) आवश्यक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चेम्प्स प्रणाली के अंतर्गत कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर, शक्ति चलित कृषि यंत्र और सिंचाई पंप रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर हेतु के लिए 07 मई 2026 से आवेदन स्वीकार किए जा रहे है। इसी प्रकार शाकम्भरी योजना के अंतर्गत सिंचाई पंपों हेतु 11 मई 2026, कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन के तहत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर एवं अन्य शक्ति चलित कृषि यंत्रों के लिए 15 मई 2026 से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक कृषक निर्धारित तिथियों पर प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे के बीच अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को की आधिकारिक वेबसाइट http://champs.cgstate.gov.in/ का उपयोग करना होगा।

फाफाडीह इलाके से 15 जुआरी गिरफ्तार 1,54,500 नगद सहित मोबाइल फोन जप्त

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के गंज पुलिस एवं रात्रि गश्त टीम ने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात में फाफाडीह इलाके से 15 जुआरियो को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1,54,500 रुपये नगद, मोबाइल फोन सहित जुआ खेलने में प्रयुक्त वाहन को जप्त किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना गंज पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गंज थाना क्षेत्र के फाफाडीह इलाके में एक मैदान में कुछ व्यक्ति रूपयों का दांव लगाकर हार-जीत का जुआ खेल रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए गंज पुलिस टीम द्वारा आस पास की अन्य टीमों के साथ तत्काल मौके पर दबिश दिया और 15 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से कुल 1,54,500 रुपये नगद, 52 नग ताश पत्ती, मोबाइल फोन एवं जुआ खेलने में प्रयुक्त वाहन को जप्त। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई। **गिरफ्तार आरोपी**- 1. सतपाल सिंह, निवासी देवेन्द्र नगर, रायपुर 2. गजेन्द्र कुमार साहू, निवासी डीडीनगर, रायपुर 3. ओमप्रकाश चन्द्रा, निवासी सारंगढ़-बिलाईगढ़ 4. परमानंद कुर्रे, निवासी महासमुंद 5. नरेन्द्र सागर, निवासी कोतवाली क्षेत्र, रायपुर 6. दीपक पात्रे, निवासी नेहरूनगर, रायपुर 7. विक्की रोचवानी, निवासी टिकरापारा, रायपुर 8. संजय कुकरेजा, निवासी डीडीनगर, रायपुर 9. अभिषेक माणिकपुरी, निवासी टिकरापारा, रायपुर 10. ओंकार साहू, निवासी पुरानी बस्ती, रायपुर 11. बब्बू उर्फ पवन कस्तूरिया, निवासी न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर 12. कमल रञ्झेला, निवासी न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर 13. सौरभ जैन, निवासी न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर 14. मुकेश नारायणी, निवासी न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर 15. मोहित धीवानी, निवासी पुरानी बस्ती, रायपुर।

छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल देशभर के लिए प्रेरणादायी

केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान सेरीखेड़ी में अजा परियोजना और पिंक दीदी नवाचारों का किया निरीक्षण

रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज रायपुर जिले के सेरीखेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत संचालित इस केंद्र में उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और आजीविका गतिविधियों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित अजा परियोजना और बेहतर बाजार लिंकेज की प्रशंसा करते हुए इसे देशभर के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया।

मंत्री श्री पासवान ने एकीकृत बकरी पालन मॉडल अजा के क्रियान्वयन को बारीकी से देखा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ा रही है, बल्कि वैज्ञानिक पशुपालन को भी नई दिशा दे रही है। आधुनिक शेड, नियमित टीकाकरण, पशु बीमा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और जैविक खाद निर्माण जैसी व्यवस्थाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के लिए बाजार की सुलभ उपलब्धता को अन्य राज्यों के लिए भी सीखने योग्य बताया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नवा रायपुर में संचालित ई-ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी की सराहना की। उन्होंने हितग्राही महिलाओं से संवाद कर उनके अनुभव जाने और कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। एकीकृत बकरी पालन परियोजना, कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों, आजीविका सेवा केंद्र, के अलावा उन्होंने बिजनेस दीदी, मशरूम उत्पादन और कृषि आधारित अन्य गतिविधियों का भी अवलोकन किया।

मंत्री श्री पासवान ने कृषक उत्पादक समूह की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महिलाओं से आत्मीय चर्चा की। इस दौरान दीदियों ने साझा किया कि कैसे वे घर की चारदीवारी से निकलकर आज एक संगठित व्यवसाय का नेतृत्व कर रही हैं। मंत्री ने महुआ कुकीज का स्वाद लिया और समूह की दीदियों के कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र को संगठित कर लाभ अर्जित करना ही वास्तविक सशक्तिकरण है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल को अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए अधिकारियों को इन योजनाओं के और अधिक विस्तार पर जोर देने को कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आजीविका मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं महिला समूहों को बेहतर कार्य के लिए बधाई देते हुए योजनाओं के और विस्तार पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव श्री भीम सिंह, कलेक्टर श्री गौरव सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिस्वरांजन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने मल्टी यूटिलिटी सेंटर, सेरीखेड़ी (रायपुर) अजा परियोजना, पिंक दीदी ई-ऑटो, बिजनेस दीदी, एफपीओ से संवाद की और कहा कि छत्तीसगढ़ का ग्रामीण आजीविका मॉडल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले-

केंद्र सरकार के एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान सहित 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे देशभर के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। धान के एमएसपी में हुई बढ़ोतरी किसानों के सम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में देश में सबसे अधिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है।

मुख्यमंत्री साय के अनुसार किसान हितैषी नीतियों की वजह से प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है और किसानों का भरोसा सरकार पर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।

प्लांट के लिए फर्जी एनओसी : भूपेश के आरोप पर मंत्री टंकराम का पलटवार

- कहा- गांव वाले चाहे तो एनओसी दे, न चाहे तो न दें

रायपुर। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अलदा में स्पंज आयरन प्लांट लगाने के लिए ग्राम पंचायत की एनओसी का सहारा लेने के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया है। मंत्री ने कहा कि यदि गलत हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। गांव वाले चाहे तो एनओसी दें, न चाहे तो न दें।

दरअसल, एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के देवरी और अलदा के किसानों के साथ प्रेस कांफ्रेस किया था, जिसमें उन्होंने ग्राम अलदा में स्पंज आयरन प्लांट की स्थापना के लिए फर्जी एनओसी का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए स्थानीय विधायक और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को कटघरे में खड़ा किया था।

इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भूपेश बघेल वरिष्ठ नेता हैं। प्लांट लगाने का नियम है। शर्तो का विधान उन्हें मालूम है। क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना है, नहीं करना है, यह पंचायत और गांव वालों पर निर्भर करता है।

इसके साथ पेट्रोल-डीजल के लिए प्रदेश के पेट्रोल पंपों में लग रही कतार के बीच मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि वैश्विक संकट के कारण समस्या आ रही है। देश के हित में कम इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश वासियों से अपील करते हुए कहा कि जहां आवश्यक हो, वहां जाने के लिए बस का इस्तेमाल करें।

सुशासन तिहार में चमरू तिर्की को मिला वन अधिकार पत्र

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम जामा निवासी श्री चमरू तिर्की को सुशासन तिहार के दौरान वन अधिकार पत्र पुस्तिका प्रदान की गई। वन अधिकार पत्र मिलने से उनकी वर्षों पुरानी चिंता दूर हो गई और अब वे अपनी जमीन पर अधिक आत्मविश्वास के साथ खेती-किसानी कर सकेंगे। चमरू तिर्की ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि पहले भूमि संबंधी कार्यों में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वन अधिकार पत्र मिलने के बाद उन्हें अपनी जमीन पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है, जिससे खेती करना आसान होगा।

साव से मिले अंतरराष्ट्रीय शूटर दिव्यांशु

- जून में जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव से आज छत्तीसगढ़ के अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन ने मुलाकात की। श्री साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान दिव्यांशु ने अपने अब तक के खेल सफर के बारे में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने मिस्र में जूनियर वर्ल्ड कप में स्वर्णिम सफलता पर उन्हें बधाई दी। साव ने उन्हें अगले महीने जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

रायगढ़ के रहने वाले दिव्यांशु देवांगन ने पिछले महीने अप्रैल में मिस्र के काहिरा में हुए जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर रायफल शूटिंग में महाराष्ट्र की शांभवी श्रवण क्षीरसागर के साथ मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों ने मिलकर 499.9 अंक का स्कोर कर विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया। दिव्यांशु अगले महीने जून में जर्मनी के सुहल में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग में भारतीय टीम की ओर से भागीदारी करेंगे।

दिव्यांशु दिसम्बर-2025 में भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। उन्होंने हाल ही में भोपाल में हुए कुमार सुरेन्द्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है।

वे इस साल जनवरी में पुणे में हुए जूनियर सलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान पर रहे थे। उनका चयन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2026 के लिए भी हुआ है। वे केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया एथलीट के रूप में भी अधिसूचित हैं।

बेलौदी में उल्टी-दस्त के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

रायपुर। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम बेलौदी में उल्टी-दस्त के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। मरीजों की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और प्रभावित क्षेत्र में व्यापक सर्वे एवं उपचार अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर जिला सर्विलांस अधिकारी, चिकित्सकों और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों की टीम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में लगातार सक्रिय सर्विलांस और घर-घर सर्वे किया जा रहा है। बुधवार को 180 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें उल्टी-दस्त के 7 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 11 मई से अब तक कुल 56 मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 11 मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में जारी है। चार मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में भर्ती हैं, जबकि दो मरीज जिला अस्पताल में उपचाररत हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीणों से उबालकर पानी पीने, बासी एवं सड़ी-गली सब्जियों और खाद्य पदार्थों से परहेज करने तथा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने की अपील की है।

यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर 4 उर्वरक विक्रेताओं पर होगी एफआईआर दर्ज

रायपुर। राज्य शासन आगामी खरीफ सीजन में प्रदेश के किसानों को पारदर्शिता के साथ खाद मिले इसके लिए विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही रासायनिक खाद के कालाबाजारी और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के 4 उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप द्वारा संबंधित फर्मों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

इनमें उर्वरक निरीक्षक बागबाहरा एवं उर्वरक निरीक्षक सरायपाली को संबंधित फर्म मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली, मेसर्स ओम फर्टिलाइजर सरायपाली, आर. एस. ट्रेडर्स बागबाहरा एवं जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स सुनसुनिया के प्रोपराइटर के विरूद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि उक्त इन फर्मों द्वारा अनियमित रूप से 16 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 तक यूरिया उर्वरक का वितरण किया गया था। पूर्व में भी अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरण करने के कारण जिले के 26 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाईसेंस 21 दिवस के लिये निलंबित किया गया था। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में पॉस मशीन से ही उर्वरक वितरण के निर्देश दिए है।

महासमुंद जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों ने अपील की है, कि किसान अपने रकबे के अनुसार एवं पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की खरीदी करे एवं उर्वरक क्रय करते समय दुकानदार से बिल अवश्य ले तथा जो निजी विक्रेता ज्यादा कीमत पर यूरिया, डी.ए.पी. एवं अन्य उर्वरकों का विक्रय करे उसकी शिकायत संबंधित विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से करें।

बिरगांव नपा निगम क्षेत्र के नाली में मिला नवजात का शव

रायपुर। बिरगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र में गुरुवार सुबह जब नाली में एक कपड़े में लिपटा नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गया। उरला थाना पुलिस ने अज्ञात शव को कब्जा में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अंबेडकर अस्पताल लेकर आई जहां रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हो सकेगा। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी जांच-पड़ताल में जुट गई है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह कुछ राहगीरों ने नाली में कपड़े में लिपटा नवजात देखा। करीब जाकर देखने पर पता चला कि बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही उरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जन्म के बाद नवजात को नाली में फेंक दिया। हालांकि बच्चा मृत पैदा हुआ था या जन्म के बाद उसकी मौत हुई, इसका खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही इलाके के अस्पतालों, क्लीनिक और दवाई दुकानों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को यहां कौन छोड़कर गया?

मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित जनोन्मुखी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में दी गई अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विभागीय सचिवों से विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं सहित अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली एवं अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सुशासन और प्रौद्योगिकी के संबंध में क्षमता विकास योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के जरिये जानकारी दी। इसी तरह से अंतिम छोर तक शासन की योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंचाने के लिए डेटा आधारित निगरानी प्रणाली के संबंध में की जा रही कार्यवाही की प्रगति की जानकारी ली गई।

मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी भवन की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि प्राथमिक शालाओं के अतिरिक्त कक्षों में आंगनबाड़ी संचालित करने के लिए कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने विभागीय अधिकारियों को कहा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत शालाओं में जहा अतिरिक्त कक्ष नही है वहां पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराने अधिकारियों को कहा गया है। बैठक में अधिकारियों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी एवं सामान्य प्रशासन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी विभागीय अधिकारियों ने दी। इसी तरह से पर्यटन, ऊर्जा, संस्कृति, श्रम, वाणिज्य एवं उद्योग, विधि एवं विधायी, गृह, राजस्व एवं आपदा, सुशासन एवं अभिसरण एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।

बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, वित्त विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री अंकित आनंद, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी सचिव श्री भूवनेश यादव, राजस्व सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, कौशल विकास सचिव श्री बसवराजू एस., खेल एवं युवा कल्याण सचिव श्री यशवंत कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला रायपुर (छ.ग.)
प्रथम तल कक्ष क्रमांक 22 कलेक्ट्रेट परिसर
ईमेल - excise.acralpur@rediffmail.com

।। निविदा सूचना ।।

क्रमांक/आब./निविदा/2026./ रायपुर, दिनांक 13.05.2026.

जिला रायपुर अंतर्गत प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान देवेंद्र नगर, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान सारोना मार्ग एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान कचना को उक्त क्षेत्रों अंतर्गत ही नवीन भवन / परिसर में स्थानांतरित किए जाने हेतु विभाग के नियमानुसार आपत्तिरहित स्थलों पर भवन/परिसर के कानूनी मालिकों से सीलबंद निविदाएं (तकनीकी शर्तों से संबंधित दस्तावेज एवं रेट ऑफर पृथक-पृथक बंद लिफाफों में) आमंत्रित की जाती हैं। डिमांड ड्राफ्ट रू. 1180/- (रू. 1000/- एवं जीएसटी रू. 180/-) महाप्रबंधक, सी.एस.एम.सी.एल. रायपुर (**GENERAL MANAGER CSMCL RAIPUR**) के पक्ष में देय, का भुगतान कर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से कार्यालयीन समय में निविदा शर्तें / प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि :- 28-05-2026 समय अपरान्ह 02 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 28-05-2026 समय अपरान्ह 03 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि :- 28-05-2026 समय अपरान्ह 04 बजे

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त आवकारी
(वास्ते-कलेक्टर)
जिला रायपुर (छ.ग.)

जी-262700703/3

प्रधानमंत्री की सात अपीलें और नागरिक धर्म

सच्चिदानंद शेकटकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सात महत्वपूर्ण मुद्दों पर जन भागीदारी की अपील की है। इन अपीलों का संबंध केवल व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, वैश्विक तेल संकट और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री की यह अपील एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री की सात अपीलों में डीजल पेट्रोल की बचत, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा, ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता, कार पुलिंग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचाव तथा सोने की खरीद में संयम जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद को लेकर यह अपील भी की है कि कम से कम 1 वर्ष तक देशवासी सोना ना खरीदें। प्रधानमंत्री की इन सात बिंदुओं की अपील को केवल सरकारी सलाह मानकर टाल देना उचित नहीं होगा। इन्हें वर्तमान समय की राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में देखना होगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देश में शामिल है। देश अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है। ऐसे में यदि वैश्विक स्तर पर युद्ध या तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल-डीजल के संयमित प्रयोग की अपील इसी संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि नागरिक अनावश्यक वाहनों का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और कार पुलिंग को बढ़ावा दें। इससे केवल ईंधन की बचत ही नहीं होगी बल्कि प्रदूषण और यातायात की समस्या में भी कमी आएगी। यह अपील पर्यावरणीय दृष्टि से भी दूरदर्शी है। कोविड काल ने यह सिद्ध कर दिया था कि अनेक कार्य डिजिटल माध्यमों से सफलतापूर्वक संचालित किये जा सकते हैं। एक बार फिर कोविड काल में बरती गईं सतर्कताओं को लेकर प्रधानमंत्री ने पुनः वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने की बात कही है। इसका उद्देश्य केवल सुविधा नहीं बल्कि ईंधन और समय दोनों की बचत है। हालांकि यह भी सत्य है कि हर क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। निर्माण, उत्पादन, चिकित्सा और सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री की अपील को लचीले और व्यावहारिक तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। भारत में सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन यह भी सच है कि सोने का भारी आयात विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ाता है। प्रधानमंत्री द्वारा एक वर्ष तक सोना ना खरीदने या संयम बरतने की अपील आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। यह अपील सीधे तौर पर देश की विदेशी मुद्रा बचत से जुड़ी है। यदि नागरिक निवेश के वैकल्पिक साधनों की ओर बढ़ें तो इससे घरेलू पूंजी बाजार को भी मजबूती मिल सकती है। प्रधानमंत्री की इन अपीलों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का बोझ जनता पर डाल रही है जबकि समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रीय संकट के समय नागरिक सहयोग आवश्यक होता है। लोकतंत्र में आलोचना स्वाभाविक है किंतु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय हित के प्रश्नों को केवल राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। इतिहास गवाह है कि संकट के समय वही राष्ट्र मजबूत बनकर उभरते हैं जहां सरकार और समाज ने मिलकर जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री की इन सात अपीलों का मूल संदेश साझा जिम्मेदारी है। सरकार नीतियां बना सकती हैं लेकिन संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग अंततः नागरिकों के व्यवहार पर निर्भर करता है।

बंगाल में भाजपा की प्लान-बी पर टिकी नजर

अभिनय आकाश

बंगाल के इस चुनावी महासमर की असली दास्तान महज़ हार-जीत के आंकड़ों में नहीं, बल्कि एम फैक्टर के इर्द-गिर्द बुनी गई। राजनीति अब केवल ध्रुवीकरण या विकास के वादों के पुराने चश्मे से नहीं देखी जा रही। आइए डिकोड करते हैं कि आखिर ये 5 एम कैसे तय कर रहे हैं बंगाल की सियासत की नई दिशा और दशा। बंगाल की सियासत में एक बड़े युग का बदलाव हुआ है। पूरे 15 साल तक सत्ता के शिखर पर काबिज रही टीएमसी सरकार को बेदखल कर बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया है। इस महाविजय के पीछे सिर्फ चुनावी हवा का रुख नहीं, बल्कि एक बेहद सधी हुई बिसात थी। पार्टी ने जीत का ब्लूप्रिंट बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। सत्ता के शिखर तक पहुंचने का उनका प्लान-ए तो अब मुकम्मल हो चुका है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। अब नजरें बीजेपी के प्लान-बी पर टिकी हैं। यानी वह रोडमैप, जिसके जरिए बंगाल की खोई हुई अस्मिता, सांस्कृतिक साख और औद्योगिक पहचान को दोबारा वापस लाने का खाका खींचा गया है।

एम फैक्टर ने कैसे बंगाल का भविष्य तय किया

मुस्लिम फैक्टर : पश्चिम बंगाल की राजनीति में 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वह %रू% फैक्टर है, जो किसी भी दल को सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है। पारंपरिक तौर पर यह टीएमसी का पक्का वोट बैंक रहा है। लेकिन इस चुनाव में टीएमसी के इस वोट बैंक पर दोहरी मार पड़ी। पहला झटका हुमायूं कबीर ने दिया, जिन्होंने अपनी नई आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के जरिए मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंध लगाई। रही-सही कसर बीजेपी की आक्रामक ध्रुवीकरण की राजनीति ने पूरी कर दी, जिसने इस एम फैक्टर के इर्द-गिर्द एकदम नए और चौंकाने वाले सियासी समीकरण गढ़ दिए।

महिला वोटर्स : बंगाल की सियासत में इस बार महिलाओं ने ही किंगमेकर की कमान संभाल ली है। टीएमसी के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं महिलाओं को लुभाने का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड रहीं। लेकिन बीजेपी ने भी इस मोर्चे पर कड़ी घेराबंदी की। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, बीजेपी का सीधा वार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर था। संदेशखाली की घटना हो या आरजी कर का खौफनाक कांड—बीजेपी ने इन्हें महिला सम्मान का ज्वलंत मुद्दा बनाकर ममता सरकार के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव सेट कर दिया। इसी आधी आबादी को अपने पाले में करने की इस होड़ ने बंगाल के पूरे चुनावी समीकरण को बदलकर रख दिया है।

माइग्रेंट : इस बार बंगाल चुनाव में हार-जीत की एक बड़ी चाबी उन लाखों प्रवासी मज़दूरों के हाथ में भी रही, जो अक्सर चुनाव के दिन अपने घरों से दूर रहते हैं। रोज़गार के अभाव में पलायन कर चुके इन युवाओं और उनके परिवारों ने इस बार वोट डालने के लिए जिस तरह बंगाल का रुख किया, उसने सारे समीकरण बदल दिए। इसका असर इतना व्यापक था कि दिल्ली-एनसीआर और ख़ासकर नोएडा की रिहायशी सोसाइटियों में बंगाली कामगारों के छुट्टी पर जाने से कामकाज ठप पड़ गया। मज़दूरों की यह वापसी चुनाव में एक बड़ा नैरेटिव बन गई। वोट की इस अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने इन प्रवासियों को सोनार बांग्ला का विज़न दिखाकर राज्य में ही रोज़गार देने का वादा किया। इसके विपरीत, ममता सरकार ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मज़दूरों की इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार की नीतियों और वित्तीय असहयोग को ज़िम्मेदार ठहराया।

मतुआ : उत्तर 24 परगना और उसके सीमावर्ती इलाकों में सत्ता का रास्ता सीधे मतुआ समुदाय के दरवाज़े से होकर गुज़रता है। नागरिकता कानून (सीएए) की मांग इस समुदाय की सबसे बड़ी धुरी है, जिसके इर्द-गिर्द बीजेपी की पूरी राजनीति घूमती है। इस बार भी बीजेपी का पूरा ज़ोर सीएए के ज़रिए अपने इस पारंपरिक और निर्णायक वोट बैंक को एकजुट रखने पर रहा। लेकिन टीएमसी ने इस बार पूरी बिसात बदल दी। सीएए के राष्ट्रीय मुद्दे को कमज़ोर करने के लिए टीएमसी ने बहुत सधी हुई चाल चली और लोकल मुद्दों के साथ-साथ ज़मीनी स्तर पर जनता के भरोसे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसी स्थानीय रणनीति ने मतुआ बहुल इलाकों की चुनावी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है।

मोदी फैक्टर : बंगाल फतह के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार मोदी फैक्टर ही साबित हुआ। पीएम मोदी की रैलियों का आक्रामक रुख, केंद्रीय योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड और राष्ट्रीय विमर्श ने पूरी पार्टी को नए जोश से भर दिया। मोदी की व्यापक स्वीकार्यता ने नए वोटर्स को बड़ी तादाद में पार्टी से जोड़ा। ज़मीन पर जनता से सीधे कनेक्ट होने की पीएम की इस कला का एक यादगार पल झाड़ग्राम में सामने आया। जब अपने मेगा रोडशो के बीच पीएम मोदी एक आम बंगाली की तरह सड़क किनारे झालमुड़ी का लुत्फ़ उठाते दिखे, तो इस दृश्य ने साबित कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए महज़ वादे नहीं, बल्कि जनता के साथ ज़मीनी और सांस्कृतिक जुड़ाव भी उतना ही ज़रूरी है।

बंगाल के लिए भाजपा का प्लान बी

रोजगार, निवेश और सोनार बांग्ला: बंगाल की चुनावी बिसात पर इस बार सिर्फ नारों की गूंज नहीं है, बल्कि एक ठोस आर्थिक रोडमैप पेश करने की होड़ है। बीजेपी ने राज्य की जर्जर हो चुकी औद्योगिक साख को फिर से खड़ा करने के लिए कई अहम दांव चले हैं-

1. जूट उद्योग का पुनर्जागरण : बंगाल की पहचान और कभी रोजगार का सबसे बड़ा इंजन रहा जूट उद्योग, बीजेपी के मुख्य एजेंडे में है। दशकों से जंग खा रही और बंद पड़ी जूट मिलों के ताले खोलने का वादा किया गया है। योजना महज इन्हें चालू करने की नहीं है, बल्कि तकनीकी मदद और पूंजी के जरिए इन्हें हाईटेक बनाने की है, ताकि युवाओं के लिए फिर से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके।

2. युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाने की पहल : लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) में नई जान फूंकने के लिए राज्य में एक विशेष निगम बनाने की तैयारी है। इसके तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद (जिसमें ग्रांट और ब्याज-मुक्त लोन शामिल है) का प्रस्ताव रखा गया है।

3. ग्रेटर कोलकाता और वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर : पार्टी के सोनार बांग्ला विजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। कोलकाता और उसके आसपास के उपनगरों को मिलाकर एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब तैयार करना। इसके लिए लॉजिस्टिक खर्च को कम करने और निर्यात को रफ्तार देने पर फोकस है। हल्दिया पोर्ट का आधुनिकीकरण, नए डीप-सी पोर्ट का निर्माण और बेहतरीन रेल-सड़क नेटवर्क बिछाना इस रणनीति का मुख्य हिस्सा है।

4. सिंगूर का नया अध्याय, विशेष औद्योगिक जोन : उद्योग के नाम पर सियासत का केंद्र रहे सिंगूर जैसे इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का वादा है। इन पार्कों का खाका इस तरह तैयार किया गया है कि एक हिस्सा भारी उद्योगों के लिए और दूसरा हिस्सा एमएसएमई के लिए आरक्षित रहे, ताकि दोनों एक-दूसरे के पूरक बन सकें।

5. पलायन रोकना : पिछले 15 सालों में राज्य से उद्योगों के पलायन को रोकने के लिए बीजेपी ने लाल फीताशाही को खत्म कर निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाने का भरोसा दिया है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस, पारदर्शी प्रशासन और स्थिर नीतियों के जरिए प्राइवेट सेक्टर का खोया हुआ विश्वास वापस लाने की योजना है। इसके अलावा, राज्य को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने के वास्ते आईटी (आईटी) और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक सेक्टर्स पर भी खास दांव खेला गया है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

कदाचित् कोई निरा निठल्ला यह कहने का कष्ट करे कि पुराणकार बान्धा है, जिससे कि बहिन भाई इसका उत्तर यह है कि जब वेद ने इस प्रकार का भ्रामक रूपक क्यों के निवाह का तात्पर्य निकलता है, (ख) में भी यज्ञ को न केवल आलंकारिक रीति से पुरुष मात्र ही कहा है बल्कि उसके अमुक अमुक विधानों को शिर, भुख, उदर रूप से प्रकट किया है, इससे इस आख्यान की रूपकता सुस्पष्ट ही है। तब पुराणों में इसका पुरुषरूपेण वर्णन करना आक्षेप योग्य कैसे हो सकता है?

सुद्युम्न का स्त्री हो जाना

श्रीमद्भागवन (6।1।13-42) में तथा पद्मपुराण (सृ0 ख0 5। अ08) में वर्णन आता है कि सुद्युम्न नाम युवक राजकुमार पुरुष से स्त्री बन गया और उसके पेट से पुरूरवा नामक प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा की उत्पत्ति हुई, इत्यादि। शंकावादियों का कहना है कि यह आख्यान अत्यन्त असम्भव एवं सृष्टिनियम के सर्वथा विरुद्ध है। हम इस पर भी विचार करते हैं।

पौराणिक-स्वरूप

अप्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो भगवान्किल।
मित्रावरुणयोरिष्टि प्रजार्थमकरोत्प्रभुः ।।13।।
तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत ।
दुहित्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता ।।14।।
होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साऽभवत् ।
तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम् ।।16।।
अस्तौषीदादिपुरुषमिलायाः पुंस्त्वकाम्यया ।।21।।
तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः।
ददाविलाभवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः ।।22।।
स एकदा महाराज! विचरन्मृगयां वने ।।23।।
यत्रास्ते भवाञ्छर्को रममाणः सहोमया ।।25।।
अपश्यत्स्त्रियमात्मानमश्वं च वडवां नृप ! ।।26।।
स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः।।34।।

क्रमशः ...

अन्तर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

ललित गर्ग

हर वर्ष 15 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस एक मानवीय रिश्तों का उत्सव ही नहीं, बल्कि मानव सभ्यता को उसकी जड़ों की याद दिलाने का अवसर है। यह दिन हमें बताता है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक, तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित क्यों न हो जाए, मनुष्य की सबसे पहली जरूरत आज भी परिवार ही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस इस वर्ष विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, युद्ध, हिंसा, मानसिक तनाव, अकेलेपन और टूटते मानवीय विश्वासों के संकट से गुजर रही है। ऐसे कठिन समय में परिवार केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व, सुरक्षा, संस्कार और संवेदनाओं की सबसे मजबूत छत बनकर सामने आता है।

आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और नैतिक संकट है। बाजार की चकाचौंध ने आदमी को उपभोक्ता तो बना दिया, लेकिन संवेदनशील इंसान नहीं बना सकी। संबंधों में स्वार्थ का प्रवेश हुआ है। विश्वास की जगह संदेह ने ले ली है। आदमी मशीनों से जुड़ रहा है, लेकिन अपनों से कटता जा रहा है। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, वे परिवारों के भीतर भी दिखाई देने लगे हैंकृपति-पत्नी के बीच, पीढ़ियों के बीच, भाई-भाई के बीच। संवाद टूट रहे हैं, सहनशीलता घट रही है और 'मैं' का अहंकार 'हम' की भावना को निगलता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं है, वह जीवन-मूल्यों का विद्यालय है। वहीं मनुष्य पहली बार प्रेम सीखता है, त्याग सीखता है, सहयोग, अनुशासन, धैर्य और सह-अस्तित्व की भावना सीखता है। यदि परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र और विश्व भी संतुलित रहेंगे। इसलिए आज आवश्यकता केवल परिवार बचाने की नहीं, बल्कि परिवारों को मूल्यनिष्ठ बनाने की है। आज जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीवन की आवश्यकताएं महंगी होती जा रही हैं और बेरोजगारी युवाओं के सपनों को तोड़ रही है, तब संयुक्त परिवार की अवधारणा फिर प्रासंगिक बनती दिखाई दे रही है। संयुक्त परिवार केवल आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का भी आधार है। वहां संसाधनों का साझा उपयोग होता है, जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं और संकट अकेले व्यक्ति पर नहीं टूटता। अकेलेपन से उपजी अवसाद की समस्याएं संयुक्त परिवारों में अपेक्षाकृत कम दिखाई देती हैं क्योंकि वहां संवाद और अपनापन जीवित रहता है। वास्तव में आधुनिक सभ्यता ने स्वतंत्रता तो दी, लेकिन उस स्वतंत्रता ने कई बार व्यक्ति को संबंध-विहीन भी बना दिया। महानगरों के छोटे-छोटे फ्लैटों में रहने वाले हजारों लोग आर्थिक रूप से संपन्न होकर भी भीतर से बेहद अकेले हैं। वृद्ध माता-पिता उपेक्षा के शिकार हैं, बच्चे संस्कारों से दूर हो रहे हैं और पति-पत्नी के बीच संबंधों की ऊष्मा कम होती जा रही है।

बीजिंग, वाशिंगटन और गलतफहमी

ज्योति भास्कर

आज चीनी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर किए जाने वाले वायरल मीम्स में से एक है—द अमेरिकन किल लाइन। वीडियो गेम की शब्दावली से लिया गया यह शब्द उस सीमा को दर्शाता है, जहां पहुंचने पर एक कमजोर किरदार को आसानी से खत्म किया जा सकता है। यह चीन में प्रचलित उस आम धारणा की ओर इशारा करता है कि लाखों अमेरिकी परिवार तबाही के कगार पर खड़े हैं—बस नौकरी जाने, बीमारी या किसी अचानक खर्च आने की देर है, और वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। यह अमेरिका के लिए चीन में प्रचलित एक ऐसी उपमा बन गई है, जिसे आर्थिक पतन, हिंसक अपराध और अपरिवर्तनीय गिरावट में फंसा हुआ माना जाता है। जाहिर है, यह सही नहीं है।

अमेरिका में हिंसक अपराधों की दर दशकों में सबसे कम है; देश के पास बेजोड़ भू-राजनीतिक और वित्तीय शक्ति बरकरार है, और इसकी अर्थव्यवस्था आज भी जीवंत है। चीन की अर्थव्यवस्था से यह 50 प्रतिशत से भी अधिक बड़ी है। फिर भी, ट्रंप की चीन यात्रा के दरम्यान वहां एक खतरनाक किस्म का %अति-आत्मविश्वास% पनपता दिख रहा है, जो अमेरिका के पतन से जुड़ी गलत धारणाओं पर आधारित है। यह ऐसी %अड़ियल% प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते चीनी नेता अपने देश की ताकत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को ज्यादा तत्पर हो रहे हैं; और भविष्य में अमेरिका के साथ होने वाले किसी टकराव में उनके पीछे हटने की संभावना कम हो रही है।

इस वसंत में पूरे चीन में मुझे हर जगह यही बात सुनने को मिली। हाल ही में जब %किल लाइन% मीम का बेहद खौफनाक रूप सामने आया और चर्चा में रहा, तो चीन में मेरे परिवार वालों ने कहा कि उन्हें अमेरिका में रहने वाले रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है। पिछले एक दशक में अमेरिका के प्रति लोगों का नजरिया काफी हद तक बिगड़ गया, क्योंकि ट्रंप एक ऐसे अमेरिका की नुमाइंदगी करते

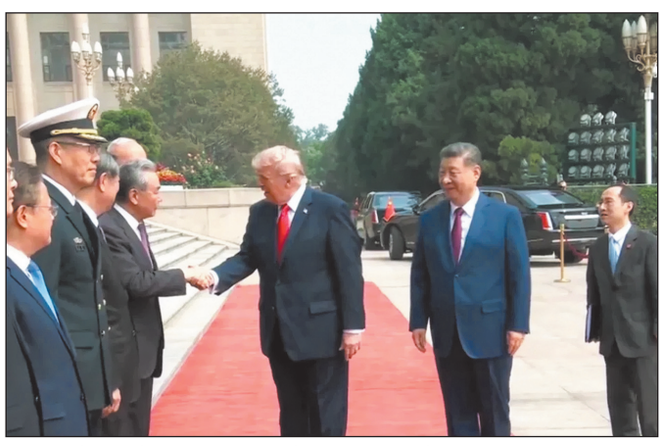

नजर आते हैं, जो अस्थिर व कमजोर है। दिसंबर में हुए एक सर्वे में सामने आया कि लगभग आधे चीनी लोगों का मानना है कि दुनिया भर में अमेरिका का असर कम हो रहा है। यह धारणा कुछ हद तक एक बचाव तंत्र है, जो चीनी लोगों को अपनी समस्याओं (जैसे, सुस्त अर्थव्यवस्था, ढहता प्रॉपर्टी बाजार, उच्च बेरोजगारी और अनिश्चितता की व्यापक भावना) से निपटने में मदद करता है।

देंग शियाओपिंग के दुभाषिए के तौर पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर झांग वेइवेइ ने जनवरी में एक वायरल वीडियो में बेतुका दावा किया कि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहां लोग अच्छा खाना खाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की बयानबाजी इस बात को और मजबूत करती है। इसके लिए बस चीन के सरकारी न्यूज चैनल पर रात की खबरें देखना काफी है- आधे घंटे के इस प्रसारण का ज्यादातर हिस्सा देश की घरेलू सफलताओं का गुणगान करता है, और आखिर के कुछ मिनटों में अमेरिका की अंदरूनी गड़बड़ियों पर बात होती है, जिसमें आजकल ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग से पैदा हुई वैश्विक उथल-पुथल का ही बोलबाला रहता है।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा जगत से %गलत% पश्चिमी बौद्धिक ढांचों (न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों का पृथक्करण) को हटाने और उनकी जगह ऐसे विचारों को लाने पर जोर दिया है, जो देशभक्ति, पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देते हैं। पहले, कई आम चीनी लोग ऐसी बातों को महज प्रोपेगेंडा मानकर अनदेखी कर देते थे। लेकिन हाल के सर्वेक्षणों और अध्ययनों से पता चलता है कि अब युवा चीनी) इसे धीरे-धीरे ज्यादा लोग (खासकर सच मानने लगे हैं। मैं 1980 के दशक में चीन में बड़ा हुआ, जब देश दुनिया के लिए खुल रहा था। हमें उम्मीद थी कि एक दिन हम फिर से महान शक्तियों की कतार में शामिल हो जाएंगे। पर एक स्पष्ट विनम्रता भी थी—मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में खुद को ढालने की एक चाहत। आज, मैं एक ऐसा चीन देखता हूं, जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली है—आत्मविश्वासी और अपने ही नियमों के अनुसार चलने को तत्पर।

अब चीनी नेता व्यापार और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका के दबाव को ऐसा खतरा नहीं मानते, जिसके लिए उन्हें कोई समझौता करना पड़े; बल्कि वे इसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आसानी से टाले जा सकने वाले दबाव के तौर पर देखते हैं। जैसा कि पिछले साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था, जब उन्होंने %रेयर अर्थ% और दूसरे जरूरी खनिजों का निर्यात रोकने की धमकी दी थी, जिसके चलते ट्रंप को टैरिफ के मामले में पीछे हटना पड़ा था। इस तरह का प्रभाव एक मुख्य कारण है कि चीन महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर पैनल जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में, और दवा निर्माण के उन कच्चे माल में (जो दुनिया की अधिकांश दवा आपूर्ति का आधार हैं) अपना वर्चस्व बनाने के लिए लगातार आक्रामक प्रयास कर रहा है। भविष्य की व्यापार वार्ताओं या किसी भू-राजनीतिक टकराव की स्थिति में, ये अब चीन के लिए %अंतिम उपाय% का काम करेंगे। जैसे-जैसे चीनी जनता का घमंड बढ़ रहा है, वैसे-वैसे देश के नेताओं के लिए दक्षिण चीन सागर या ताइवान से जुड़े संभावित संकटों के दौरान संयम दिखाने की राजनीतिक कीमत भी बढ़ती जा रही है। पिछले साल गेम-थ्योरी पर हुई एक रिसर्च से पता चला कि राष्ट्रवाद में जरा-सी भी बढ़ोतरी होने पर, इस बात की संभावना काफी बढ़ जाती है कि किसी भी टकराव की स्थिति में चीन और अमेरिका, दोनों ही ज्यादा आक्रामक रुख अपना लेंगे।

यह रुझान ऐसा नहीं है, जिसे पलटा न जा सके। चीन के प्रति अमेरिका की नीति को फिर से दो बातों पर केंद्रित किया जाना चाहिए- एक, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना (जैसे कि अहम आपूर्ति शृंखला में अमेरिका की मजबूती बढ़ाना और एशिया में अपनी भू-राजनीतिक मौजूदगी को सशक्त करना) और दूसरा, उन मानवीय संबंधों को फिर से बहाल करना, जिन्होंने कभी इस रिश्ते को जोड़े रखने में मदद की थी और दोनों पक्षों को अपनी-अपनी जानकारी के दायरे में सिमटने से रोका था। यह एक सरल, लेकिन संभावित रूप से प्रभावी शुरुआती कदम होगा कि वाशिंगटन चीनी छात्रों और विद्वानों के लिए वीजा और सुरक्षा संबंधी बाधाओं को कम करे, और पर्यटन, शिक्षा तथा व्यापार के क्षेत्रों में आदान-प्रदान को बढ़ावा दे।

ट्रंप ने नौ साल पहले अपने पहले कार्यकाल में चीन का दौरा किया था। यात्रा में इतना लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। अमेरिका का निरंतर, स्पष्ट और दृढ़ जुड़ाव ही शायद चीनी गलतफहमियों को दूर करने और दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।

आज का इतिहास

1878 टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गयी।
1891 पोप लियो XIII ने विश्वकोशीय ररम नोवेरम जारी किया, जिसमें मजदूर वर्गों की दशा थी और इसे आधुनिक कैथोलिक सामाजिक शिक्षण की नींव रखने के लिए माना जाता है।
1891 फिलिप्स एंड कंपनी को हॉलैंड में स्थापित किया गया।
1905 लॉस वेगास (साल्ट लेक लेक रेलरोड) के स्वामित्व वाले 110 एकड़ (0.45 किमी 2) के बाद लास वेगास (स्वागत चिन्ह चित्र) रेलरोड के रूप में स्थापित किया गया था।
1916 जेसी वाशिंगटन, एक किशोर अफ्रीकी-अमेरिकी फार्महैंड, वाको, टेक्सास, यूएस में रंजित था, जो नस्लीय प्रेरित लिंचिंग का एक प्रसिद्ध उदाहरण बन गया।
1918 अमेरिका में पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत।
1919 विन्निपेग जनरल स्ट्राइक हुई, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की लगभग पूरी कामकाजी आबादी ने 15 मई, 1919 को कनाडा के विन्निपेग में हड़ताल में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी।
1928 मिक्की और मिन्नी माउस ने एनिमेटेड फिल्म प्लेन क्रेजी में अपनी फिल्म की शुरुआत की।
1930 विश्व की पहली महिला एयरहोस्टेस ऐलन चर्च ने ऑकलैंड-शिकागो फ्लाइट में उड़ान भरी।
1939 श्री चिप्स द्वारा बनायीं गयी रोमांटिक नाटक फिल्म अलविदा का ब्रिटेन में प्रीमियर किया गया।
1940 मैक और डिक मैकडोनाल्ड नाम के दो भाइयों ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डीनो में मैकडोनाल्ड रेस्त्रां की शुरुआत की।
1948 ऑस्ट्रेलिया ने एसेक्स के खिलाफ क्रिकेट मैच में एक दिन में 721 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया।
1953 डॉन मर्फी ने अमेरिका के ब्वॉय स्काउट्स के क्यूबस्काउट्स के लिए पहला पाइनवुड डर्बी का आयोजन किया, जहां थ्रेसआउट द्वारा निर्मित लकड़ी की कारों को चलाया जाता है।
1957 ब्रिटेन ने 15 मई, 1957 को प्रशांत महासागर के माल्डेन द्वीप में ऑपरेशन ग्रेप्ल के तहत अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और इसके बाद ब्रिटेन थर्मोन्यूक्लियर शक्ति बन गया। ब्रिटेन ने एच-बम के पहले परीक्षण को लघु ग्रेनाइट का नाम दिया।
1963 गॉर्डन कूपर, एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, 15 मई, 1963 को बुध-एटलस 9 अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में उतारा गया था। यह पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का अंतिम मिशन था जिसे प्रोजेक्ट मर्करी कहा गया और गॉर्डन अंतरिक्ष में सोते हुए पहले अमेरिकी बन गए। 34 घंटे का मिशन।

वैश्विक संकट के दौर में दूरगामी सोच का परिणाम है प्रधानमंत्री की अपील

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

ऐसा नहीं है कि भारत विदेशी मुद्रा के मामलें में संकट में हो बल्कि वास्तविकता तो यह है कि 10 अप्रेल, 2026 के आंकड़ों की ही बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार आज उच्चतम स्तर पर है। 700 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक का विदेशी मुद्रा भण्डार भारत के पास है। एक मोटे अनमुन के अनुसार आगामी 11 माह से अधिक समय तक आयात मांग की पूर्ति इस राशि से आसानी से हो सकती है। विदेशी मुद्रा भण्डार से एफसीए यानी कि विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भण्डार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित राशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पर इसके सबके बावजूद भविष्य के संभावित संकट के हालातों से निपटने की आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाती है तो यही दूरदृष्टि कहलाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भविष्य के वैश्विक हालात साफ दिखाई दे रहे हैं। हालातों में सुधार की संभावना निकट भविष्य में दिखाई भी नहीं दे रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केवल एक वर्ष के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती का आग्रह देशवासियों से किया है। इसमें ईंधन बचाना, सोना नहीं खरीदने, विदेशी यात्राओं व विदेशों में शादी नहीं करने, खाने के तेल के उपयोग में 10 प्रतिशत तक की कटौती व खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक की कटौती करने का सुझाव प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशवासियों से आग्रह को लेकर आलोचक भले ही मुद्दा बनाने का प्रयास करें पर वैश्विक हालात आज सबके सामने हैं। देशवासियों को मालूम है कि पेट्रोलियम उत्पादों इनमें कच्चे तेल से लेकर गैस आदि आदि शामिल है आदि के लिए आयात पर निर्भरता अधिक है। देश में 979 अरब अमेरिकी डॉलर का सालाना आयात होता है जिसमें से करीब 38 प्रतिशत आयात केवल और केवल पेट्रोलियम पदार्थों पर ही हो रहा है। सोना-चांदी और इलेक्ट्रोनिक्स के साथ ही फर्टिलाइजरों के मामलें में भी विदेशों पर निर्भरता अधिक है। करीब 10 प्रतिशत राशि सोने के आयात पर खर्च होती है। यदि समग्र रुप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के सिकन्दराबाद से देशवासियों से जो आग्रह किया है वह ऐसा नहीं है जो किसी भी तरह से देशवासियों के लिए दुबिधाजनक हो।

वैश्विक संकट के चलते देश-दुनिया की इकोनोमी पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देशवासियों से दूरदृष्टियुक्त अपील से कोरोना काल की याद ताजा हो रही है तो पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लालबहादुर शास्त्री की तत्कालीन अन्न संकट के दौरान सप्ताह में एक

दिन के उपवास के आग्रह की और चला जाता है। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध सीज़फायर के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो दूसरी और दोनों ही देशों की हठधर्मिता के कारण हार्मुज जलडमरुमध्य से परिवहन बाधित होने का परिणाम दुनिया के देशों के सामने हैं। दुनिया के देशों को यह समझ लेना होगा कि अमेरिका-ईरान युद्ध केवल दो या तीन देशों के बीच युद्ध तक सीमित ना होकर इसके असर से आज कोई देश दूर दूर तक अछूता नहीं दिखाई दे रहा है। यह दो देशों की अहम् की लड़ाई ना होकर समूची मानवता को प्रभावित करने वाले हालात है। आज दुनिया के देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है। बिना किसी अन्य देश के सहयोग के कोई भी देश अपने स्तर पर अपने देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। आर्थिक उदारीकरण के बाद से आज विश्व विश्व ग्राम में परिवर्तित हो गया है। एक बात यह भी साफ हो जानी चाहिए कि आज अमेरिका-इजरायल और ईरान संकट का हल निकल भी आता है तब भी वैश्विक हालात सामान्य होने में लंबा समय लग जाएगा। युद्धरत देश यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि उनके अहम् के चलते दुनिया आज सालों पीछे जा रही है। विकास बाधित हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है और हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं।

आज सबको मालूम है कि अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात प्रभावित हो रहा है। हार्मुज का रास्ता अवरुद्ध है। हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि ईरान को प्रतिदिन 2800 करोड़ रुपए के कच्चे तेल को समुद्र में बहाना पड़ रहा है। तेल उत्पादक अन्य देश भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने, सार्वजनिक परिवहन वाहनों के उपयोग और वाहन पूलिंग का एक साल का सुझाव या आग्रह दूरदृष्टिपूर्ण व देशहित में ही माना जाना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का बढ़ावा देना भविष्य के पर्यावरण संकट से बचाव और हरित उर्जा को बढ़ावा देने में ही सहायक हो सकेगा।

इसी तरह से हमारे देश में सोने के खरीद के प्रति खास मोह रहता आया है पर हालातों को देखते हुए व्यापक राष्ट्रहित में एक साल के लिए सोना नहीं खरीदे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से केवल शानों शोकत के लिए विदेशी यात्राएं करने से बचने की सलाह और विदेशों में शादी करने के स्थान पर स्थानीय पर्यटन और देश में ही एक से एक बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशंस पर शादी करने से जहां खर्च कम होगा, देश के डेस्टिनेशनों की वैश्विक पहचान के साथ ही विदेशी पूंजी भी बचेगी। इसी तरह से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से खेती और खेतों की उर्वरा शक्ति प्रभावित होने से आज देश दो चार हो रहा है।

जैविक खाद और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने का आग्रह निश्चित रुप से सकारात्मक ही है। जहां तक मीटिंग्स का प्रश्न है कोविड़ के बाद से सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर अधिकांष मीटिंग्स अब हाईब्रीड मोड पर ही होने लगी है। वर्कफ्राम होम को अवश्य प्रोत्साहित किया जा सकता है।

लब्बो-लबाब यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो देशवासियों से आग्रह किया है उनमें से एक भी ऐसा आग्रह नहीं है जिससे हमारे दैनिक जीवन चर्या प्रभावित हो रही हो। एक भी ऐसा बिन्दु नहीं है जिससे आमजन प्रभावित हो रहा हो। सीधे सीधे एक साल के लिए अपनी आदत व आवश्यकताओं में जरुरी बदलाव के लिए कहा जा रहा है ताकि वैश्विक संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था व देश के आमलोगों को प्रभावित ही ना कर सकें। एक साल सोना नहीं खरीदने या ईवी वाहन या सार्वजनिक वाहन का उपयोग या विदेशों में शादी आदि कार्यक्रम आयोजित ना करने या विदेश घूमने नहीं जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला हैं। इसलिए इन सबसे बचने से देश वैश्विक हालातों का अधिक कुशलता से मुकाबला कर सकेगा और सबसे बड़ी बात की स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आलोचना प्रत्यालोचना से ऊपर उठना होगा। यह देश नेता की एक आवाज पर आगे आना वाला देश है कोविड का समय और स्व. लालबहादुर शास्त्री के एक दिन के उपवास का आग्रह इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है।

धर्मनिरपेक्षता की मृगतृष्णा में भटक रहा इंडिया गठबंधन तोड़ रहा है सियासी दम?

कमलेश पांडे

धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा मूलत: सर्वधर्म समभाव और राज्य की धार्मिक निष्पक्षता पर आधारित रही है। लेकिन पिछले कई दशकों में भारतीय राजनीति के एक हिस्से ने इसे सामाजिक संतुलन के बजाय अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के राजनीतिक औजार के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि आज अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल वैचारिक संकट से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। सच कहूं तो वे सभी धर्मनिरपेक्षता की मृगतृष्णा में भटक रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस की बेरुखी से अपना अपना सियासी दम तोड़ते जा रहे हैं!

जहां कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक खुद को धर्मनिरपेक्ष राजनीति की केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित रखा। परंतु समय के साथ उस पर यह आरोप मजबूत होता गया कि उसने बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और वोट बैंक आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और बहुसंख्यक अस्मिता के प्रश्न को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया।

आज स्थिति यह है कि जो दल कभी भाजपा के हिंदुत्व विमर्श का तीखा विरोध करते थे, वे भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मंदिर, सनातन परंपरा, जातीय-सामाजिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रवाद की भाषा बोलने लगे हैं। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय मतदाता अब केवल धर्मनिरपेक्षता के पारंपरिक नारों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह सांस्कृतिक आत्मसम्मान और विकास के संतुलन की अपेक्षा कर रहा है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वह अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि उसकी

राजनीति की मूल दिशा क्या होगी—पारंपरिक अल्पसंख्यक केंद्रित गठजोड़?

सामाजिक न्याय आधारित नई राजनीति? या फिर भारतीय सांस्कृतिक चेतना के साथ सामंजस्य? यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल समय रहते अपने वैचारिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन नहीं करते, तो उनके सामने तीन बड़े खतरे बने रहेंगे—

पहला, बहुसंख्यक समाज से लगातार बढ़ती दूरी उनके लिए सियासी चिंता का सबब बन सकती है। क्योंकि क्षेत्रीय दलों द्वारा उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाया जा चुका है। दूसरा, भाजपा के राष्ट्रवादी विमर्श के सामने वैकल्पिक नैरेटिव का अभाव उतपन्न हो गया है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय लोकतंत्र केवल बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक राजनीति पर नहीं चलता। तीसरा, अंतत: जनता विकास, सुशासन, सुरक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आत्मविश्वास—इन सभी का संतुलन चाहती है।

इसलिए भविष्य उसी राजनीतिक शक्ति का होगा जो पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर विश्वसनीय शासन मॉडल प्रस्तुत कर सके। कांग्रेस के लिए चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक प्रासंगिकता बचाने की है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि वह अपने पुराने ढांचे से बाहर निकलकर नई राजनीतिक भाषा गढ़ पाती है या नहीं।

हरियाणा निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत

नीरज कुमार दुबे

तीन राज्यों में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा नगर निकाय चुनावों में भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति एक बार फिर साबित कर दी है। दस मई को हुए मतदान के बाद बुधवार को घोषित परिणामों में पार्टी ने छह जिलों की सात प्रमुख सीटों में से छह पर जीत दर्ज की। इस जीत को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और संगठन की मजबूत रणनीति की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों में महापौर पद पर शानदार जीत हासिल की। अंबाला में पार्टी उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने भारी मतों से विजय प्राप्त की। यहां बीस वार्डों में से सोलह पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस को केवल तीन सीटें मिलीं और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। पंचकूला में भी भाजपा का दबदबा देखने को मिला, जहां श्याम लाल बंसल ने महापौर पद जीता। बीस वार्डों में भाजपा ने सत्रह सीटों पर विजय हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल एक सीट जीत सकी और दो सीटें निर्दलीयों के खाते में गईं।

सोनीपत में भाजपा उम्मीदवार राजीव जैन ने महापौर पद पर जीत दर्ज कर पार्टी की स्थिति और मजबूत कर दी। हालांकि यहां वार्ड चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाईस में से सत्रह वार्ड जीत लिए, जबकि भाजपा को पांच वार्डों पर संतोष करना पड़ा। इसके बावजूद महापौर पद पर भाजपा की जीत को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रेवाड़ी नगर परिषद में भाजपा उम्मीदवार वनीता पीपल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। हालांकि यहां वार्ड स्तर पर निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा और बत्तीस में से बीस वार्डों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की। भाजपा को ग्यारह वार्ड मिले जबकि कांग्रेस केवल एक वार्ड जीत सकी। धारूहेड़ा नगरपालिका में भी भाजपा उम्मीदवार सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने नौ हजार तीन सौ बानवे मत प्राप्त किए जबकि

उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी बाबूलाल लांबा को तीन हजार एक सौ छप्पन मत मिले। यहां अध्यक्ष पद भाजपा ने जीता, लेकिन सभी अठारह वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए।

सांपला नगरपालिका में भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में अध्यक्ष पद जीतकर राजनीतिक हलकों को चौंका दिया। यहां सोलह वार्डों में भाजपा को छह सीटें मिलीं जबकि शेष दस सीटें निर्दलीयों ने जीतीं। उकलाना नगरपालिका में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की। यहां सभी सोलह वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीते।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। पूरे राज्य में लगभग 54.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कुल आठ लाख तिहत्तर हजार एक सौ सतहत्तर मतदाताओं में से लगभग चार लाख पचहत्तर हजार नौ सौ अड़तालीस मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मतदान प्रतिशत की बात करें तो रोहतक में सबसे अधिक उन्यासी दशमलव दो प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यहां पंद्रह हजार छह सौ चौबीस मतदाताओं में से लगभग बारह हजार तीन सौ बहत्तर लोगों ने मतदान किया। हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र में पचहत्तर दशमलव पांच प्रतिशत मतदान हुआ था जबकि रेवाड़ी में छियासठ दशमलव एक प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था।

उधर, इन चुनाव परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है, विशेष रूप से उस समय जब हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी को एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की आक्रामक चुनावी रणनीति, बूथ स्तर तक मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी ने कई क्षेत्रों में लगभग नब्बे प्रतिशत वार्ड सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता के भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने इसे राज्य की दोहरे इंजन वाली सरकार पर जनता के विश्वास का प्रतीक बताया और जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह परिणाम जनता के विश्वास और जनकल्याणकारी नीतियों की जीत है। उधर, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और उसे अच्छा जनसमर्थन मिला है।

बहरहाल, कांग्रेस की लगातार तीन हरियाणा विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में हार का कारण आंतरिक गुटबाजी और पार्टी संगठन पर सिर्फ हुड्डा परिवार का वर्चस्व होना बताया जा रहा है। खास बात यह है कि मतदान से ठीक पहले हरियाणा के गुरुग्राम में राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाल कर राज्य का सियासी माहौल बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उन्हें विफलता ही हाथ लगी।

अब घुसपैठ से मुक्त होगा पश्चिम बंगाल

सुरेश हिंदुस्तानी

पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तौर पर शुभेन्दु अधिकारी ने शासन की बागडोर संभाल ली है। भाजपा का यह स्पष्ट नारा रहा है कि वह विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। इसलिए पश्चिम बंगाल के जनादेश में इस पर अब जनता की मुहर भी लग गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देकर अपने शासन का संचालन किया। इसमें बांग्लादेश के घुसपैठियों का भी समर्थन भी शामिल रहा। अब भाजपा की सरकार बनने के बाद यह तय हो चुका है कि अब पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगी हुई सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी और एक बड़ी समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। इससे यह भी आशय निकलता है कि सबका साथ और सबका विकास वाली राजनीतिक अवधारणा को स्वीकार किया जाने लगा है। देश में इसी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता है। क्योंकि राजनीतिक दलों ने आज देश में रहने वाले समाज के बीच इतना भेद पैदा कर दिया है कि कई जगह समाज बंधु एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हिन्दू और मुसलमान समाज के ही हिस्से हैं, इसलिए इनको अलग अलग देखने की राजनीति नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत देश के कुछ राजनीतिक दलों का आधार ही मुस्लिम वोट हैं। जबकि यह भी सही है कि तुष्टिकरण से किसी का भला न तो हुआ है और न ही होगा।

लम्बे समय से पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का अप्रत्याशित रूप से बढ़ना कई प्रकार के सवाल खड़ा करता रहा है। इसके पीछे बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भी एक बड़ा कारण है। इस समस्या से बंगाल ही नहीं, असम भी प्रभावित है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विपक्षी राजनीतिक दलों को यह समस्या दिखाई नहीं देती। असम और पश्चिम बंगाल की जनता इस घुसपैठ के विरोध में खड़ी हो गई है, इसलिए इस बार का जनादेश भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में आया। इसी के चलते असम में भाजपा सरकार का पुन: बनना और पश्चिम बंगाल में एक नए राजनीतिक उदय के साथ सत्तारूढ़ होना इसी बात का परिचायक है कि भाजपा ही

नहीं, जनता भी देश से घुसपैठियों को निकालने का मन बना चुकी है। सुनने में यह भी आ रहा है जो बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करके आए, वे अपने देश वापस जाने का मानस बना चुके हैं। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल घुसपैठ की समस्या से मुक्त हो जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में प्रारंभ से ही इस बात पर जोर दिया था कि वह विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ है। भाजपा के नेताओं के भाषण भी इसी पर केंद्रित रहते थे। इस मुद्दे पर भाजपा को जनता का भी समर्थन मिला और जनता ने भाजपा को बहुमत दे दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किए, वह कहीं न कहीं हिन्दू समाज को नीचा दिखाने वाले ही थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता शायद इस बात को भूल गए कि बहुसंख्यक समाज को नकारने की राजनीति एक प्रकार से उसके लिए सत्ता से अलग होने की तस्वीर पेश कर सकती है।

पश्चिम बंगाल घुसपैठ की समस्या से बहुत प्रभावित हुए हैं। यहां पर अप्रत्याशित रूप से ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कई जगह अचानक ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनते जा रहे हैं। जिनमें मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा आदि है। यह तीनों जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। इसके चलते बंगाल में अपराध भी बहुत होने लगे हैं। इसका कारण यही माना जा रहा है कि जो व्यक्ति घुसपैठ करके आए हैं, उनके सामने रोजगार का संकट है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति गलत कार्य भी करने लगता है। इससे की दशा और दिशा भी ख़राब हो रही है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रास्ते कई बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करते रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की मदद से वे सभी अपने आशियाने भी बना रहे थे, इनके ज्यादातर आशियाने अवैध कब्ज़ा करके ही बने हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के समय इनको पर्याप्त संरक्षण भी मिला। उल्लेखनीय है जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों की जनसंख्या अचानक बढ़ी है, वे सभी तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में हिन्दू समाज का कोई भी व्यक्ति जाने से डरता है। सवाल यह है कि यह डर किसने पैदा किया और इसको संरक्षण देने वाले कौन हैं। तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राह पर चलते हुए इनको ताकत देने का काम किया। और यही उसकी हार का कारण भी बना।

अब पश्चिम बंगाल का राजनीतिक दृश्य परिवर्तित हो चुका है। जिन्होंने लम्बे समय तक अमानुषिक अत्याचार सहन किए, वे सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन भाजपा को यह सत्ता ऐसे ही नही मिल गई। उसके सैकड़ों कार्यकर्ता का बलिदान इस जीत के नींव के पत्थर बने। चुनाव के बाद शुभेन्दु अधिकारी के निजी सहायक देवनाथ की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कार्य प्रशिक्षित अपराधियों ने किया। संभावना इस बात की भी है कि घटना के बाद ये बांग्लादेश भाग चुके हैं। इसे राजनीतिक हत्या के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसके आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं।

घुसपैठियों की समस्या से त्रस्त पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद विदेशी घुसपैठिओं के चेहरे उतरने लगे हैं, क्योंकि अब इन विदेशी घुसपैठियों को सहन नहीं किया जाएगा। अब उनको बाहर जाना ही होगा। भाजपा की सरकार ही इनको बाहर निकलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे हैं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि भाजपा ने केवल घुसपैठियों को बाहर निकालने की ही बात की है, भारत के मुसलमानों की नहीं, लेकिन विपक्ष और खासकर तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि सारे मुस्लिमों पर इसका प्रभाव होगा। विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना सभी चाहते हैं, विपक्ष को इस मुद्दे पर भाजपा का साथ देना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय हित की बात है।

पश्चिम एशिया संकट और भारत की भूमिका

अनिल त्रिगुणायत

ईरान पर युद्ध थोपने के महीना भर बाद अमेरिका हांफने लगा है और इसके सबूत दिखने लगे हैं। कई अमेरिकी विमानों को मार गिराने के ईरान के दावों पर अगर विश्वास न किया जाये, तो भी कम से कम एक अमेरिकी विमान को निशाना बनाने और एक अमेरिकी पायलट के गायब होने की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उसे अमेरिका ने ढूंढ लिया है। यह भी स्पष्ट है कि ईरान को नेस्तनाबूद करने की अमेरिकी आक्रामकता अब होर्मुज जलडमरुमध्य को खोलने की जिद पर अड़ गयी है, लेकिन यूरोप के देश अब ट्रंप की महत्वाकांक्षा के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। पहले साठ देशों ने होर्मुज के मुद्दे पर एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें अमेरिका और चीन मौजूद नहीं थे, लेकिन भारत की मौजूदगी थी। उसमें यह प्रस्ताव जारी किया गया कि होर्मुज को खोलने का काम युद्ध के जरिये नहीं, बल्कि संवाद के जरिये ही हो सकता है। फिर अमेरिका और अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमलों के जरिये होर्मुज को खोलने संबंधी प्रस्ताव दाखिल किया, लेकिन फ्रांस, रूस और चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। ईरान पर अमेरिका-इस्राइल के हमले पर यूरोप के देश पहले ही सहमत नहीं थे। लेकिन होर्मुज के मुद्दे पर तो यूरोप के साथ रूस और चीन भी अमेरिका के साथ खड़े नहीं हैं। जैसे-जैसे युद्ध खिंचता जा रहा है, इसे शुरू किये जाने की व्यर्थता सामने आ रही है। खाड़ी देशों का ही उदाहरण लें, तो वे बेकार ही इस युद्ध में फंस गये। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमले को अंजाम देता है, तो खाड़ी देशों को भीषण नुकसान होने की आशंका है। ईरान दरअसल वर्षों से अमेरिकी और इस्राइली युद्ध तकनीकों का गहराई से अध्ययन करता रहा है। उसने उसी के अनुरूप अपनी रक्षा तैयारियां कर रखी हैं। यही कारण है कि अमेरिका और इस्राइल की सैन्य तथा तकनीकी श्रेष्ठताओं तथा ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के अमेरिका-इस्राइल के दावों के बावजूद आइआरजीसी (इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स) लगातार न सिर्फ लड़ रहा है, बल्कि दुश्मन देशों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। बेशक अमेरिकी ताकत के आगे ईरान का कोई मुकाबला नहीं है। ईरान की युद्ध रणनीति जीत हासिल करने की है भी नहीं, वह तो एक राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखने और शत्रु देशों के लिए जीत को बेहद मुश्किल और खर्चीला बना देने की नीति पर काम कर रहा है। ईरान के पिट्ठू हिजबुल्लाह पहले से ही मैदान में थे। फिर इस्राइल के खिलाफ हूथी विद्रोही भी कूद पड़े। इससे इस्राइली रक्षा क्षमता पर दबाव बढ़ा है और आम इस्राइली भी नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका-ईरान के बीच के वार्ताकार और ओमान के विदेश मंत्री हमाद अल बुसैदी ने 'द इकोनॉमिस्ट' में लिखा कि 'अमेरिका अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण खो चुका है'। उन्होंने इस्राइल पर भी गलत अनुमान लगाने और ट्रंप को एक घातक युद्ध में धकेल देने का आरोप लगाया है। वाशिंगटन देर-सबेर अगर इस युद्ध में विजयी होने की घोषणा करे, तो भी उसके परिणाम दुनिया को अगले अनेक वर्षों तक भुगतने पड़ेंगे। इस युद्ध से जुड़े ट्रंप के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान पर एकतरफा हमला करने तथा युद्ध में साथ न देने वाले यूरोपीय नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के कारण अमेरिका तेजी से अपनी साख, अपने दोस्त और समर्थक खोता जा रहा है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह ट्रंप अब भी अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है, 'ईरान के खिलाफ यह अभियान खत्म हो जाने के बाद हमारी दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी', जबकि वास्तविकता इसके विपरीत दिखती है। यह ठीक है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश फिलहाल रणनीतिक संयम बरतने के बावजूद अमेरिका और इस्राइल के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ओमान, कतर और कुवैत का मानना है कि ईरान चूंकि पड़ोसी देश है, लिहाजा उसके साथ उसी तरह का रवैया अपनाना पड़ेगा। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी अंदरूनी समीकरण खाड़ी देशों के बीच अलगाव और तनाव बनाये रखेंगे। ईरान के कमजोर होने से इस्राइल की ताकत निस्संदेह बढ़ेगी। ट्रंप यह चाहते भी है, लेकिन अरब और मुस्लिम देशों में खासकर निचले स्तरों पर इस्राइल के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। इस कारण भी युद्ध के बाद की दुनिया अशांत ही रहने वाली है। चीन, रूस और भारत जैसे देशों के लिए, जिनके अपने गहरे भू-राजनीतिक, भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक हितों के कारण ईरान और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), दोनों से बेहतर संबंध हैं।

हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण

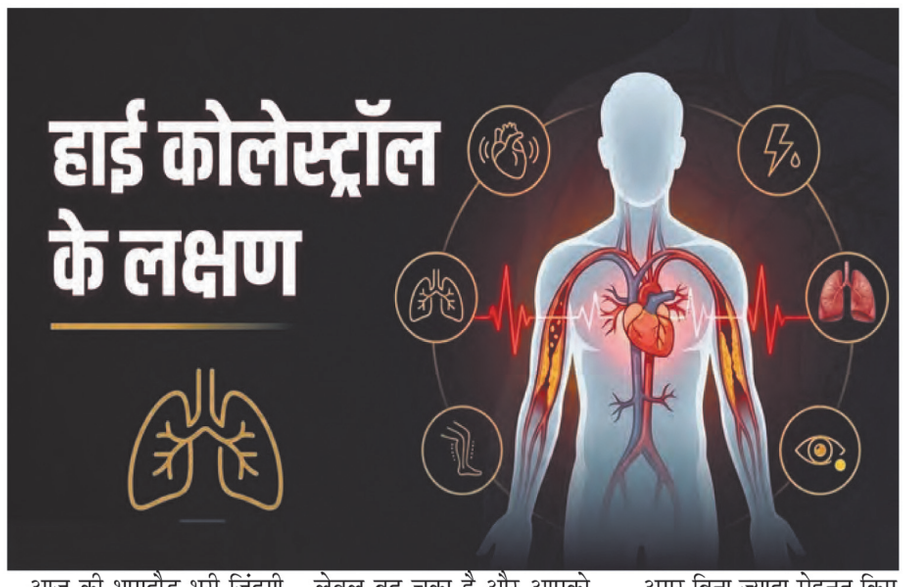

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी खानपान की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम लेकिन खतरनाक समस्या बनती जा रही है। अक्सर लोग इसे तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक कोई बड़ी परेशानी सामने न आए।

पर क्या आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे हमारी नसों में जमने लगता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। अगर शरीर पहले ही कुछ चेतावनी संकेत देने लगे तो समय रहते इसे पहचानकर सुधार करना बहुत जरूरी हो जाता है।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से संकेत बताते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है और आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है, ताकि समय रहते आप अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकें।

सीने में दर्द या भारीपन

जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ जाता है, तो यह धीरे-धीरे नसों की दीवारों पर जमने लगता है। इससे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दिल तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से सीने में दबाव, जलन या भारीपन जैसा महसूस हो सकता है। कई बार यह दर्द चलने-फिरने या सीढ़ियां चढ़ने पर बढ़ जाता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

बार-बार थकान

अगर बिना ज्यादा मेहनत किए भी शरीर जल्दी थक जाता है, तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। नसों में ब्लॉकेज होने से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही तरीके से

नहीं पहुंच पाते। इससे व्यक्ति को हर समय कमजोरी, सुस्ती और एनर्जी की कमी महसूस होती है।

पैरों में सुन्नपन या दर्द

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर पैरों की नसों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। इसके कारण पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या हल्का दर्द महसूस हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने या चलने के बाद यह समस्या और बढ़ सकती है। यह संकेत बताता है कि शरीर में ब्लड फ्लो सही नहीं है।

आंखों के आसपास पीले धब्बे

कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल का असर त्वचा पर भी दिखाई देता है। खासकर आंखों के आसपास छोटे-छोटे पीले या सफेद धब्बे बन सकते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में xanthomas कहा जाता है। यह शरीर में फैट जमा होने का स्पष्ट संकेत हो सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

सांस लेने में दिक्कत

जब नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, तो दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हल्की फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी सांस फूलने लगती है। सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ा चलना भी भारी लग सकता है। यह संकेत दिल और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है।

प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने वाले हो जाएं सावधान!

आजकल ज्यादातर लोग घर, ऑफिस, जिम और यात्रा के दौरान पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। हल्की और आसानी से उपलब्ध होने की वजह से ये बोतलें लोगों की पहली पसंद बन गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है?

खासकर गर्मी के मौसम में जब प्लास्टिक की बोतल धूप या ज्यादा तापमान के संपर्क में आती है, तो ये और भी ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन शरीर पर बुरा असर डाल सकता है।

इसलिए यह समझना जरूरी है कि प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल कितना सुरक्षित है और किन सावधानियों को अपनाकर इसके नुकसान से बचा जा सकता है। इस लेख में हम आपको इसी से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे।

पानी में घुल सकते हैं हानिकारक केमिकल

प्लास्टिक की बोतल जब तेज धूप, गर्मी या ज्यादा तापमान के संपर्क में आती है, तो उसमें मौजूद केमिकल पानी में घुलने लगते हैं। इनमें BPA और माइक्रोप्लास्टिक जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन करने से शरीर के अंदर टॉक्सिक तत्व जमा हो सकते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

हार्मोन पर पड़ सकता है असर

कुछ प्लास्टिक बोतलों में BPA (Bisphenol-A) नाम का केमिकल पाया जाता है, जो शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। यह केमिकल शरीर में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन की नकल करता है, जिससे हार्मोनल असंतुलन की समस्या हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असर महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा पड़ सकता है।

बार-बार इस्तेमाल करना खतरनाक

जो प्लास्टिक बोतलें एक बार उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें बार-बार इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता। बार-बार उपयोग करने से बोतल की सतह पर छोटे क्रैक पड़ सकते हैं, जिनमें बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। सही तरीके से सफाई न होने पर ये बैक्टीरिया पेट दर्द, संक्रमण और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

इम्यूनिटी पर असर

लगातार प्लास्टिक बोतलों में रखा पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक और केमिकल्स धीरे-धीरे शरीर में जमा होकर कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इससे शरीर संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में कमजोर पड़ सकता है।

क्या झगड़ा करने से पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है

पति-पत्नी के बीच का रिश्ता बेहद खास होता है। इस रिश्ते में किसी तीसरे के बीच में आने की कोई गुंजाइश नहीं होती। पर, कई बार ऐसा होता है कि पति-पत्नी के बीच होने वाले झगड़े को लोग काफी गलत तरीके से ले लेते हैं। जबकि उनके बीच होने वाला झगड़ा उनके बीच के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाता है।

जी हां, सही पढ़ा आपने। वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि पति-पत्नी को आपस में लड़ना नहीं चाहते, इससे रिश्ता कमजोर होता है पर, ऐसा नहीं है।

असल जिंदगी में अगर आपके और आपके पार्टनर बीच झगड़ा होता है तो इससे आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इतना ही नहीं कई बार तो लड़ाई के बाद आपस में और ज्यादा प्यार बढ़ता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये झगड़ा ज्यादा बढ़े नहीं क्योंकि ज्यादा झगड़ा बढ़ने से चीजें बिगड़ सकती हैं।

दिखती है एक-दूसरे की केयर

लड़ाई के वक्त हम अक्सर एक दूसरे को कह देते हैं कि आपको हमारी फिक्र नहीं है। पर, जब लड़ाई होती है उसके बाद जब आपका पार्टनर आपकी केयर करता है तो इससे आपका दिल भी पिघल जाता है।

बाहर आती है दिल की बात

कई बार गुस्से में हम वो बोल देते हैं तो शायद नॉर्मल रहते हुए नहीं बोल पाते। पति-पत्नी के रिश्ते में अक्सर लोग लड़ाई से बचने के लिए बातों को मन में रखते हैं। इससे चीजें और खराब हो जाती हैं। झगड़े के वक्त मन की बाते बाहर आती हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होता है।

बढ़ता है भरोसा

जब पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता है और लड़ाई शांत होने का बाद जब वो बात करते हैं, और चीजों को सुलझाते हैं तो इससे उनके बीच भरोसा बढ़ता है।

झगड़े में सामने आता है असली व्यवहार

झगड़े में इंसान का असली व्यवहार सामने आता है। इससे लोगों की अनफिल्टर्ड भावनाएं भी सामने आती हैं, जो पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं।

ज्यादा गुस्सा आना कहीं आपको न कर दे बीमार? शरीर पर पड़ता है ऐसा गंभीर असर

गुस्सा आना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी प्रकार के खतरे, अन्याय या कुंठा के कारण आपको गुस्सा आ सकता है। गुस्सा कुछ पल में अपने आप कम भी हो जाता है, लेकिन अगर यही गुस्सा बार-बार, ज्यादा तीव्रता के साथ या लंबे समय तक बना रहे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। बार-बार गुस्सा आना या फिर हमेशा गुस्से में ही रहना आपके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है।

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार बार-बार गुस्सा आने से मानसिक तनाव, चिंता, नींद की समस्या और रिश्तों में दूरी जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अध्ययनों में ज्यादा गुस्सा आने को दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाला भी बताया गया है। इस दौरान हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव भी होते हैं जिस वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।

आइए जानते हैं ज्यादा गुस्सा आने से क्या-क्या दिक्कतें होती हैं?

बार-बार गुस्सा आना सेहत के लिए ठीक नहीं

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि गुस्सा केवल मानसिक प्रतिक्रिया नहीं है, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।

गुस्से के दौरान सिरदर्द, मांसपेशियों में तनाव, पेट दर्द या तेजी से सांस लेने जैसी समस्याएं महसूस होती हैं।

अगर यह स्थिति लगातार बनी रहे तो हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है।

अगर किसी को बार-बार गुस्सा आता है और ये कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो सावधान हो जाएं और डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है असर

गुस्सा आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ज्यादा गुस्सा दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि गुस्से की स्थिति में दिमाग की तार्किक शक्ति कम हो जाती है, जिससे सही फैसले लेना कठिन हो जाता है।

अक्सर गुस्सा करने वाले लोगों में एंजायटी, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादा गुस्सा आपके तनाव लेवल को भी बढ़ा देता है जिससे मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है।

ब्लड प्रेशर पर बढ़ता है खतरा

जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो शरीर में एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन तेजी से रिलीज होते हैं। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार बार-बार गुस्सा आने की आदत हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा सकती है।

ज्यादा गुस्से के दो घंटे के भीतर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। गुस्से के दौरान रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

ज्यादा गुस्सा आने से होने वाले इन साइड-इफेक्ट्स को भी जानिए

अध्ययनों में पाया गया हैं कि जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है उनके नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। नींद की कमी याददाश्त, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित कर देती है।

ज्यादा गुस्सा और लगातार तनाव से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा रहता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित हो सकती है।

क्या आप जानते हैं ज्यादा गुस्से का असर आपके पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। गुस्से के दौरान पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है।

आप व्याकुलता और बेचैनी की समस्या से जूझ रहे हैं

जब कभी आपके दिमाग में कोई नया विचार आता है तो सबसे पहले क्या आप यह सोचते हैं कि इसमें क्या गलत हो सकता है? जब कभी संवाद अस्पष्ट होता है, तो क्या सबसे पहले आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं? अगर ऐसा है, तो आप अपने विचारों को बदलना सीख सकते हैं जिससे कि वो आपकी सोच को सीमित न कर दें। काम के दौरान होने वाली व्याकुलता और बेचैनी कैसे परेशानी का सबब बनती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, यहां जानिए...

लोगों के प्रति मन में गलत धारणा बनाते हैं

ज्यादातर बेचैन लोगों के मन में यह चलता रहता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं और न ही उनके हुनर की कद्र करते हैं। उनके मन में खुद को लेकर कोई न कोई शंका हमेशा बनी ही रहती है। जरूरी है कि हमेशा अपने विचारों पर पहरा रखें। देखें कि कब आपके विचार बिना किसी वजह के ही नकारात्मक हो रहे हैं। ध्यान दें कि कब आप बिना किसी ठोस सबूत के ही अपनी धारणाएं बनाने लगते हैं।

फीडबैक से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं

बेचैन लोग फीडबैक को विपत्ति की तरह देखते हैं। वो उसे अपनी असफलता का सूचक भी मानते हैं। वो मानते हैं कि फीडबैक उनकी नाकामी को साबित करने का एक जरिया मात्र है। यह देखें कि आप किस तरह फीडबैक लेना पसंद करते हैं। ओपन फीडबैक लेने का सबसे आसान तरीका खोजें। अगर फीडबैक आपको असहज या उदास करे तो कहें- अच्छी बात है, मैं इन बिंदुओं पर विचार करूंगा।

सबकी नजर में मुश्किल व्यक्ति बन जाते हैं

बेचैन लोग अक्सर उन चीजों से बचना चाहते हैं, जो उन्हें असहज करती हैं और फिर वो अपने रवैए से शर्मिंदा भी होते हैं। जैसे किसी ईमेल का जवाब देने में असहज महसूस कर सकते हैं तो टालमटोल करने लगते हैं। इससे आपके गैर जिम्मेदार होने की धारणा भी बन जाती है। अच्छा ये होगा कि आप जिस चीज से असहज हो जाते हैं उसके बारे में सबको पहले ही ईमानदारी से बता दें।

नए विचारों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं

अगर नए विचारों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया रिस्क और फेल्युअर से जुड़ी है, तो लोग आपको एक नकारात्मक व्यक्ति की तरह देखने लगेंगे। इसके बजाय यह देखने की कोशिश करें कि उस नए विचार से क्या बेहतर हो सकता है। इसके बाद ही अपनी चिंता व्यक्त करें। लेकिन आखिर में अपनी बात को सकारात्मक नोट पर खत्म करें। प्रतिक्रिया देने की जल्दी कभी न करें। बहुत सोच-समझकर जवाब दें।

कितने दिन में बदल लेना चाहिए कूलर का पानी?

गर्मी का मौसम आते ही लोग परेशान नजर आते हैं, क्योंकि पारा चढ़ने लगता है और जलती-चुभती गर्मी लोगों को परेशान करने लगती है। इसलिए लोग कूलर चलाते हैं और आज भी एक बड़ी संख्या में लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं।

कूलर में अगर पानी भरकर चलाया जाए तो ये काफी ठंडी हवा देता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कूलर में पानी भरने के कितने दिन बाद इसे बदल देना चाहिए और नया पानी भरना चाहिए? शायद नहीं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कूलर में पानी भरने के कितने दिन बाद इसे बदल देना चाहिए...

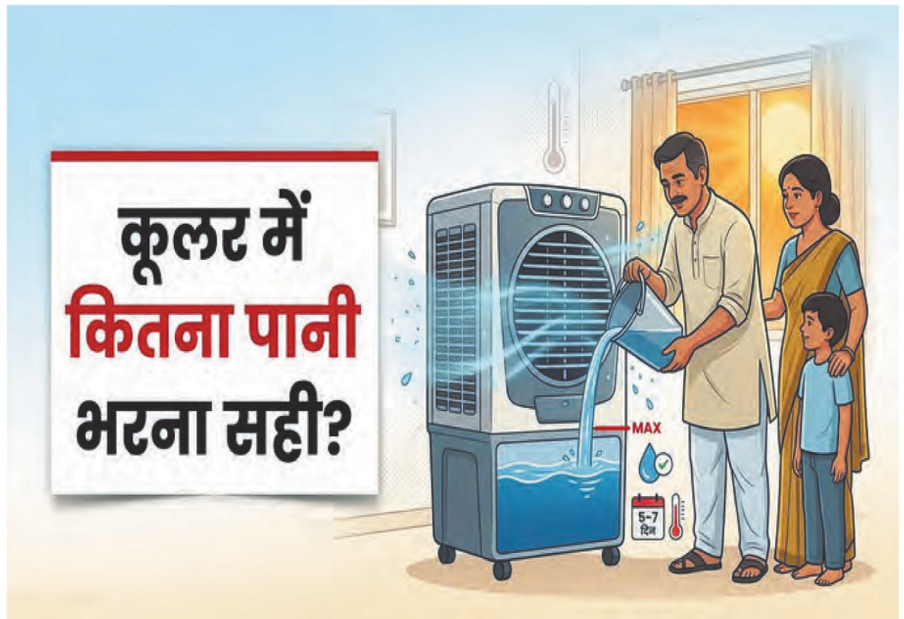

क्यों जरूरी है कूलर में पानी भरना?

कूलर में पानी भरना विकल्प होता है यानी अगर आप चाहें तो बिना पानी के भी कूलर चला सकते हैं

पर बिना पानी के कूलर ठंडी हवा नहीं देता

इसलिए पानी भरने पर कूलर की घास यानी पैड गीले होते हैं जिससे कूलर से ठंडी-ठंडी हवा आती है

कितने दिन में बदल देना चाहिए कूलर का पानी?

एक बार पानी भरने के बाद वैसे तो 2-2 दिन में पानी बदल देना चाहिए

पर कम से कम 5-7 दिनों के भीतर पानी को जरूर बदल लेना चाहिए और नया पानी भरना चाहिए

पानी कम होने पर दोबारा पानी भरा जा सकता है

पानी भरना ही कूलर में काफी नहीं

जब पानी भरें तो इस दौरान कूलर के टैंक को अच्छे से साफ कर लें

पानी के पाइप को साफ कर लें और ये सुनिश्चित करें कि पाइप में कुछ फंसा न हो

कूलर में कितना पानी भरना चाहिए?

कूलर में पानी को अधिकतम लेवल वाले निशान तक भरना चाहिए

अगर आप लोहे का कूलर इस्तेमाल करते हैं तो ढक्कन के नीचे एक पट्टी लगी होती है, वहां तक पानी भर सकते हैं

कूलर में टंकी का गर्म पानी भरने की जगह नॉर्मल पानी भरें, जो आपको ठंडी हवा देने में मदद कर सकता है

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

वकील की ड्रेस में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार सुबह वकील की पोशाक पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचीं। जानकारी के मुताबिक, वह विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका मामले में चीफ जस्टिस सुजॉय पाल की बेंच के समक्ष दलीलें पेश करने पहुंची हैं।बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी अदालत की कार्यवाही के कई पहलुओं पर सवाल उठा सकती हैं। उनके हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अदालत परिसर में राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई। लंबे समय बाद किसी बड़े राजनीतिक नेता को स्वयं अदालत में पेश होकर बहस करते देखना चर्चा का विषय बन गया है। यह जनहित याचिका टीएमसी नेता और वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय के बेटे शीर्षान्या बंदोपाध्याय द्वारा दायर की गई थी। ममता बनर्जी इससे पहले भी कानूनी मामलों में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं।

राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति, सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ से मांगी रिपोर्ट

लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों से जवाब तलब किया है। बीजेपी नेता एस विग्नेश शिशिर ने याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की है। उन्होंने कोर्ट से इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ को नोटिस जारी कर मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कह दिया है।

पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकते: राजनाथ

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया है और कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अब पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकती। श्री सिंह ने गुरुवार को यहां प्रमुख रणनीतिक संवाद कलम और कवच में अपने वर्चुअल संदेश में कहा कि इस मंच का नाम ही देश के भविष्य के सुरक्षा ढांचे की सशक्त दृष्टि को दर्शाता है। कवच शक्ति, सुरक्षा और राष्ट्र की रक्षा करने की क्षमता का प्रतीक है। वैश्विक संघर्षों के बदलते स्वरूप पर सिंह ने कहा कि दुनिया भर में रणनीतिक परिदृश्य लगातार अधिक अनिश्चित, प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी-आधारित होता जा रहा है। उन्होंने भू-राजनीतिक तनाव, संघर्ष, साइबर खतरे, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी और हाइब्रिड युद्ध के उभरते स्वरूपों को देशों के सामने मौजूद प्रमुख चुनौती बताया।

नेता विपक्ष की भूमिका बस दिखावा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देश में चुनाव आयोग के शीर्ष पदों मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा कि मौजूदा चयन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रभाव इतना अधिक दिखाई देता है कि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत सीईसी और ईसीएस की नियुक्ति प्रक्रिया तय की गई है। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है और मामले की अगली तारीख पर आगे विचार किया जाएगा। वर्तमान कानून के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

अपील का विरोध: हर चीज में असहयोग करती है कांग्रेस : साय

रायपुर। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण डीजल-पेट्रोल की खपत कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कांग्रेस को रास नहीं आई है. इस पर उठे विरोध के स्वर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस हर चीज में असहयोग करती है. देशहित पीएम मोदी जो भी अच्छा करते हैं, कांग्रेस उसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण जो स्थिति चल रही है, उसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने पेट्रोल-डीजल का खपत कम करने का आह्वान किया है. हम भी उस पर अमल कर रहे हैं, हमने भी अपना करकेट में गाड़ियों की संख्या कम दिए हैं। वहीं दिल्ली प्रवास की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा भी साथ में हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. बस्तर में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान चला रहे है. अग्रणी बस्तर अभियान चला रहा है. लोगों के कार्ड बनवा रहे हैं,।

केरल कांग्रेस में बगावत के सुर!

मुख्यमंत्री पद न मिलने से रमेश चेन्निथला नाराज

तिरुवनंतपुरम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने गुरुवार को केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में वी.डी. सतीशान के नाम की घोषणा के बाद नाराजगी व्यक्त की। इस घोषणा के साथ ही कई दिनों से चल रही अटकलों और अनिश्चितताओं का अंत हो गया। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी से फोन आने के बावजूद रमेश चेन्निथला असंतुष्ट रहे। सूत्रों ने बताया कि वे विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेंगे और मंत्रिमंडल में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वरिष्ठता को उचित महत्व नहीं दिया गया है। हालांकि, उनके करीबी नेताओं ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि चेन्निथला ने हाई कमांड के समक्ष कोई असहमति व्यक्त नहीं की है। इससे पहले दिन में, कांग्रेस ने वी.डी. सतीशान को केरल का अगला मुख्यमंत्री नामित किया। इस फैसले की घोषणा यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल की एआईसीसी प्रभारी दीपा दासमुंसी, राज्य के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक, साथ ही संचार प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने की।

मुख्यमंत्री पद के लिए तीन मुख्य दावेदार सतीशान, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला थे। दासमुंसी ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा दल की बैठक 7 मई, 2026 को तिरुवनंतपुरम में हुई थी और सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे को राज्य में विधानसभा दल के नए नेता की नियुक्ति का अधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि इसी के अनुरूप, कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एआईसीसी पर्यवेक्षकों (जिन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की थी) और सांसदों सहित कई अन्य नेताओं और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्षों के साथ व्यापक चर्चा की है।

यह घोषणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की खर्गे से लगभग 40 मिनट की मुलाकात के एक दिन बाद आई है, जिसके बाद पार्टी ने कहा कि उच्च कमान की सभी विचार-विमर्श और चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। केरल के अगले मुख्यमंत्री का फैसला 4 मई से लंबित था, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में कांग्रेस के 63 विधायक हैं। उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के 22, केरल कांग्रेस (केईसी) के आठ और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी) के तीन विधायक हैं।

जयललिता की पार्टी का भविष्य खतरे में

पलानीस्वामी का अड़ियल रुख एआईएडीएमके को ले डूबा

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार का विधानसभा चुनाव एक बड़े राजनीतिक भूचाल के रूप में सामने आया है। चुनाव परिणामों के बाद अन्नाद्रमुक के भीतर तेज होती बगावत ने पार्टी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसका अस्तित्व ही संकट में दिखाई दे रहा है। कभी तमिलनाडु की सबसे प्रभावशाली ताकतों में गिनी जाने वाली अन्नाद्रमुक अब अंदरूनी कलह, नेतृत्व संकट और टूट की आशंका से जूझ रही है।

12 मई को पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पडी पलानीस्वामी का जन्मदिन था, लेकिन यह दिन उनके लिए राजनीतिक संकट से भरा साबित हुआ। अन्नाद्रमुक विधायक दल के लगभग तीस विधायकों ने एसपी वेलुमणि और सीवी शण्मुगम का साथ दिया और पलानीस्वामी के नाम का समर्थन करने से इंकार कर दिया। इसके बाद इस गुट ने अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम नेता जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। विधानसभा में अब पलानीस्वामी और वेलुमणि को अलग-अलग पंक्तियों में सीटें दी गई हैं, जो पार्टी में स्पष्ट विभाजन का संकेत माना जा रहा है।

हालांकि पलानीस्वामी पांच विधायकों को वापस अपने पक्ष में लाने में सफल रहे, फिर भी स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं रही। कुल पच्चीस विधायकों ने विजय के पक्ष में मतदान किया जबकि केवल 22 विधायक टीवीके सरकार के खिलाफ रहे। इससे यह साफ हो गया कि विधायक दल पर पलानीस्वामी की पकड़ कमजोर हो चुकी है और पार्टी के भीतर उनका बहुमत समाप्त होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बगावत केवल विधायक दल तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच लगातार हार को लेकर गहरा असंतोष है। वर्ष 2019 के बाद यह अन्नाद्रमुक की चौथी बड़ी चुनावी हार मानी जा रही है। पार्टी के भीतर यह भावना मजबूत हो रही है कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक लगातार कमजोर हुई है और अब नए नेतृत्व की आवश्यकता है।

पलानीस्वामी पर सबसे बड़ा आरोप यह लग रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पार्टी की विचारधारा से ऊपर रखा। चुनाव परिणामों के बाद उन्होंने द्रमुक के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी। बागी नेताओं का कहना है कि यह कदम अन्नाद्रमुक की मूल विचारधारा के खिलाफ था क्योंकि पार्टी संस्थापक एमजी रामचंद्रन और जे. जयललिता ने हमेशा द्रमुक को अपना प्रमुख राजनीतिक विरोधी माना था। कार्यकर्ताओं के बीच भी यह संदेश गया कि तीसरे स्थान पर रही पार्टी सत्ता पाने के लिए दूसरे स्थान की पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हो गई।

पलानीस्वामी की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने पहले ओ पन्नीरसेल्वम पर द्रमुक का साथ देने का आरोप लगाया था। पन्नीरसेल्वम को पार्टी में वापसी की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने द्रमुक का रुख किया। उस समय पलानीस्वामी ने उन्हें द्रमुक की बी टीम तक कहा था। लेकिन अब वही पलानीस्वामी सत्ता के लिए द्रमुक के समर्थन को स्वीकार करने को तैयार दिखे, जिससे उन पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगे हैं। इस बीच बागी गुट ने एक नई राजनीतिक रणनीति अपनाई है। उनका कहना है कि जनता का जनादेश टीवीके के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री विजय के लिए है।

राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी

नजर उठाई तो वो होगा जो अब तक नहीं हुआ

नागौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को पड़ोसी देश पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि यदि उसने फिर से भारत के ऊपर नजर उठाने की जुर्रत करने की कोशिश की ''तो जो अब तक नहीं हुआ है वह होकर रहेगा।'' सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हम आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं के 'आपरेशन सिंदूर' ने नया इतिहास बनाया है। रक्षामंत्री नागौर के मेड़ता कस्बे में राजपूत शासक राव दूदा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा,''शायद पाकिस्तान फिर से भारत की ओर नजर उठाने की जुर्रत ना करे और आज आपको इस धरती से बतलाकर जा रहा हूं कि यदि पाकिस्तान ने फिर से भारत के ऊपर नजर उठाने की जुर्रत करने की कोशिश की तो जो अब तक नहीं हुआ है वह होकर रहेगा।'' उन्होंने कहा,''प्रारम्भ से ही हमारी नीति रही है... हम किसी को छेड़ते नहीं है लेकिन हमको यदि कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं हैं।'' पहलगाम आतंकी हमले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा। उन्होंने कहा, ''हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि जाति या धर्म मजहब के आधार पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ और इनसानियत में विश्वास रखते हैं लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी आकर, लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से भून रहे थे।''

सिंह ने कहा, ''पूरा देश इस घटना से आक्रोशित था। उसके बाद हमने ऐसा करारा जवाब दिया कि दुश्मन के होश ही उड़ गए। हमने यह साबित कर दिया कि अब भारत चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा है। अब अगर कोई हमारे नागरिकों पर हमला करेगा, तो अब हम उसके घर में घुसकर जवाब देंगे। यह संदेश हमने दे दिया।'' उन्होंने कहा,''जिस तरह से हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारी सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कम मिला कर चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किये हैं। हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है अब आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त नहीं की नीति की होगी। हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

फ्रेडरिक सोयेज बने जूनियर हॉकी टीम के नए कोच

मुंबई। पीआर श्रीजेश की जगह अब फ्रांस के अनुभवी कोच फ्रेडरिक सोयेज भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच होंगे। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को इस नियुक्ति का आधिकारिक ऐलान किया। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पूर्व गोलकीपर श्रीजेश का अनुबंध पिछले साल चेन्नई और मदुरै में हुए एफआईएच जूनियर वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतने के बाद समाप्त हो गया था। हालांकि पांच टूर्नामेंट में पांच पदक जीतने के बावजूद हॉकी इंडिया ने उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया। श्रीजेश ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपनी निराशा जाहिर की थी। उन्होंने संकेत दिया था कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनका अनुबंध नहीं बढ़ाया गया। हालांकि हॉकी इंडिया ने इस फैसले को 2036 ओलंपिक की तैयारियों से जोड़ते हुए कहा कि संगठन लंबी अवधि के लिए मजबूत और टिकाऊ हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम बनाना चाहता है। फ्रेडरिक सोयेज यूरोप के सबसे अनुभवी हॉकी कोचों में गिने जाते हैं। उन्होंने 1995 से 2010 तक फ्रांस के लिए 196 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 195 गोल दागे। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने उनकी नियुक्ति पर कहा, हम हॉकी इंडिया परिवार में फ्रेडरिक सोयेज का स्वागत करते हैं। उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का शानदार अनुभव है और उनका कौशल भारतीय हॉकी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा, हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले नतीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए मजबूत कोचिंग ढांचा और खिलाड़ियों का बड़ा पूल तैयार करना चाहते हैं। दिलीप टिर्की ने बताया कि हॉकी इंडिया सभी स्तरों पर भारतीय और विदेशी कोचों को साथ जोड़कर काम कर रही है ताकि खिलाड़ियों के विकास और रणनीति में निरंतरता बनी रहे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 790 अंक उछला निफ्टी 23,690 के करीब बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। फार्मा, हेल्थकेयर और मेटल शेयरों में हुई खरीदारी के चलते बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में निफ्टी 50 277.00 अंक यानी 1.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,689.60 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 789.74 अंक यानी 1.06 प्रतिशत चढ़कर 75,398.72 पर बंद हुआ। पूरे सत्र में खरीदारी का रुझान देखने को मिला, खासकर आखिरी घंटों में बाजार में तेजी और मजबूत होती गई। निफ्टी 50 के प्रमुख शेयरों में अदाणी एंटरप्राइजेज, सिप्ला और भारती एयरटेल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इन स्टॉक्स में दिनभर मजबूत खरीदारी रही, जिससे इंडेक्स को ऊपर जाने में मदद मिली। ब्रॉडर मार्केट में रुझान थोड़ा अलग रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.12 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर अचानक लगाई रोक

नईदिल्ली। देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है यानी अब भारत से विदेशों में चीनी भेजना आसान नहीं होगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि अब चीनी का निर्यात प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 13 मई को जारी अधिसूचना में कहा कि कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका को सीएक्सएल और शुल्क दर कोटा (ञ्जक्रक्त) व्यवस्था के तहत होने वाले निर्यात पर यह फैसला लागू नहीं होगा।

अप्रैल में 8.3 प्रतिशत पर पहुंची थोक महंगाई दर

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर में भारी उछाल दर्ज किया गया है। मार्च महीने में थोक महंगाई दर 3.88 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो अप्रैल में तेजी से बढ़कर 8.30 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इस जबरदस्त वृद्धि के पीछे मुख्य कारण ईंधन, बिजली और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में आई बेतहाशा तेजी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, अप्रैल 2026 में महंगाई की यह सकारात्मक दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातुओं, अन्य विनिर्माण और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण है।

मुंबई में महंगी हुई सीएनजी 84 रु. किलो मिलेगी गैस

मुंबई। मुंबई महानगर क्षेत्र में गुरुवार से सीएनजी के नए दाम लागू हो गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने सीएनजी की कीमत में दो रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। नई दर लागू होने के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत एमएमआर के कई इलाकों में अब सीएनजी 84 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। इससे पहले उपभोक्ताओं को एक किलो सीएनजी के लिए 82 रुपये चुकाने पड़ते थे। सीएनजी की कीमत बढ़ने का असर सीधे तौर पर उन लाखों लोगों पर पड़ने वाला है जो रोजाना ऑटो और सीएनजी वाहनों से सफर करते हैं। मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा हिस्सा सीएनजी पर निर्भर है, ऐसे में किराए बढ़ने की संभावना भी तेज हो गई है। सीएनजी की दरें बढ़ते ही ऑटो रिक्शा यूनियनों ने किराया संशोधित करने की मांग उठा दी है।

अब बाजार का अनुभव बदल गया है, घर पर मिनटों में पहुंच रहा जरूरी सामान

मधुरेन्द्र सिन्हा

भारत में उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री लंबे समय से हो रही थी, लेकिन जब कोविड महामारी फैली, तो फिर इसमें जबर्दस्त तेजी आई। तब लोगों को समझ में आया कि आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन क्या जादू कर सकता है। कच्चे माल की आपूर्ति, कारखानों में तैयार उत्पादों को डीलरों तक भेजना और फिर ग्राहकों तक पहुंचाना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देश के किसी भी कोने से कहीं भी कोई सामान खरीदा-बेचा जा सकता है और यह कमाल कर रही हैं ई-कॉमर्स कंपनियां। इन्होंने देश ही नहीं, दुनिया में व्यापार करने का तरीका बदल दिया।

यह ऐसा व्यापार है, जिसमें ग्राहकों को विक्रेता का पता नहीं होता, पर यह यकीन होता है कि उसे सही चीज सही कीमत पर मिल रही है। अगर पसंद नहीं है, तो सामान वापस। इसके अलावा सुरक्षित भुगतान। यानी ग्राहकों को मालूम है कि उसका पैसा सुरक्षित है। इनकी डिलिवरी भी बहुत तेज और समय पर होती है। यह ऐसी दुनिया है, जिसमें ग्राहक राजा है, क्योंकि उसे एक ही चीज के सैकड़ों विकल्प मिलते हैं। यही कारण है कि 2024 में भारत का ई-कॉमर्स बाजार 147.3 अरब डॉलर का हो गया और इसमें 18.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो मार्ट, टाटा क्लिक वगैरह ऐसी कंपनियां हैं, जो अरबों रुपये का सामान बेचती हैं और उनके ग्राहक लगातार बढ़ते हैं।

भारत में स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सस्ते होने से लोगों के सोचने व खरीदारी के तरीके बदलने के चलते यह बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ये कंपनियां सुई से लेकर मोटर कार तक ऑनलाइन बेच रही हैं। अब इनकी पैठ छोटे शहरों तक हो गई है। उम्मीद है कि 2027

तक ई-कॉमर्स के 40 करोड़ ग्राहक होंगे। एक अनुमान है कि 2030 तक इनकी कुल बिक्री 250 से 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसने देश में खपत को बढ़ावा दिया है, जिसका सकारात्मक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

स्वदेशी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की शुरुआत एक किताबों की दुकान के रूप में हुई थी, जो एक व्यापक ऑनलाइन बाजार के रूप में विकसित हुई। इसने कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) जैसी क्रांतिकारी सुविधाएं पेश कीं, जिन्होंने ऑनलाइन खरीदारी को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। व्यापार के इस खेल मे अब क्रिक कॉमर्स कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसी कंपनियां मिनटों में जरूरी सामान ग्राहकों के घर पर पहुंचा देती हैं। इसी का नतीजा है कि ये ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अब टक्कर दे रही हैं। इनके कारोबार में वृद्धि सालाना 40 फीसदी की दर से हो रही हैं और एक मोटे अनुमान के अनुसार, इस साल इनका कुल कारोबार लगभग सात अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कॉर्नेल एससी जॉनसन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिक कॉमर्स का भारत में कारोबार इस साल (2026) बढ़कर 65,645.40 करोड़ हो गया है। 2022 की तुलना में यह बढ़ोतरी 24 गुना है। बेन ऐंड कंपनी की एक रिपोर्ट बताती है कि क्रिक कॉमर्स कंपनियों के ऑर्डर 2024 में उल्लेखनीय तरीके से बढ़े। देश के कुल ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर का दो-तिहाई क्रिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हुआ था।

ई-कॉमर्स बाजार में क्रिक कॉमर्स कंपनियों ने पकड़ बना ली है, क्योंकि लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारा ई-कॉमर्स परिदृश्य देश की दृढ़ता, नवाचार और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों से लेकर सिख एक्सेसरीज डॉट कॉम जैसे विशिष्ट प्लेटफॉर्म तक, ने उपभोक्ता अनुभव को नया रूप देने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में अपना अनूठा योगदान दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनियां बड़े पैमाने पर रोजगार दे रही हैं। पीआईएफ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों ने पिछले साल 1.58 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। इनमें 35 लाख महिलाएं हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां आम वेंडरों की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं।

रायपुर में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉकः कलेक्टर डॉ. गौरव

■ कालाबाजारी पर कलेक्टर कॉल सेंटर के नंबर पर सूचित करें

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ऑयल कंपनियों के संचालकों और डीलर्स की बैठक ली। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि आम जनता को परेशानी न हो, पेट्रोल पंप से उन्हें नियमित रूप से डीजल एवं पेट्रोल की आपूर्ति होती रहे। ऑयल कंपनी की डिपो अपने डीलर्स को बिना विलंब के पेट्रोल-डीजल की सप्लाई करें। साथ ही डिपो द्वारा जो अब तक पेट्रोल-डीजल सप्लाई का समय सुबह 7 से दोपहर 3 तक था उसे स्थिति सामान्य होते तक समय बढ़ाया जाए।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने शहर के अंदर ईंधन के टैंकर को 24 घण्टे आवाजाही करने के भी निर्देश दिए। ताकि किसी भी पेट्रोल पंप में ईंधन की कमी न हो और स्टॉक रहे। साथ ही पेट्रोल पंप अधिकतम समय तक खोला जाए ताकि आम जनता को पेट्रोल-डीजल लेने में सुविधा हों। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में आमजनता को पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में गड़बड़ी न हो एवं कालाबाजारी की शिकायत न हो, ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा कि जिले में पेट्रोल-डीजल के पर्याप्त स्टॉक हैं आम जनता पैनिक न हों, और आवशकतानुसार ही पेट्रोल-डीजल की खरीदी करें, पैनिक-बाईंग न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। कालाबाजारी की सूचना मिलने पर कलेक्टर कॉल सेंटर के नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584 एवं 9977222594 पर सूचित करें।

प्रदेश एवं जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने अपील की है कि आम जनता परेशान न हों, अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही पेट्रोल-डीजल की खरीदी करें, और सहयोग करें। बैठक में खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा एवं सभी ऑयल कंपनी के अधिकारी एवं डीलर्स उपस्थित थे।

पेट्रोल-डीजल की प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक मौजूदः खाद्य सचिव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरों के बीच राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने आम लोगों से अफवाहों से बचने और पैनिक खरीदारी नहीं करने की अपील की है, सरकार और ऑयल कंपनियां मिलकर सभी पेट्रोल पंपों तक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं।

खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य में वर्तमान समय में पेट्रोल का 45,474 किलोलीटर और डीजल का 84,654 किलोलीटर स्टॉक उपलब्ध है, जबकि प्रदेश में पेट्रोल की दैनिक खपत 3,635 किलोलीटर और डीजल की दैनिक आवश्यकता 5,873 किलोलीटर है, उन्होंने कहा कि ऑयल डिपो को लगातार आवश्यकतानुसार आपूर्ति मिल रही है और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.प्रदेश में कुल 2516 पेट्रोल-डीजल पंप संचालित हैं, रायपुर में 326 पंपों में से 35 और बिलासपुर में 156 पंपों में से 13 पंप फिलहाल अस्थायी रूप से ड्राई आउट हैं,खाद्य विभाग के मुताबिक इन सभी पंपों तक तेजी से स्टॉक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और ऑयल कंपनियों के डिपो से लगातार सप्लाई भेजी जा रही है.विगत दो दिनों में कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने की खबरों के बाद लोगों में घबराहट की स्थिति बनी, इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल खरीदा, जिससे कुछ स्थानों पर कृत्रिम कमी जैसी स्थिति दिखाई दी,खाद्य सचिव ने कहा कि यह स्थिति केवल अचानक बढ़ी मांग की वजह से बनी और प्रदेश में किसी प्रकार की वास्तविक कमी नहीं है। खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने आम नागरिकों से अपील की है, कि वे किसी भी अफवाह या भ्रम में आकर ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करें,उन्होंने कहा कि शासन और ऑयल कंपनियां पूरी तरह समन्वय के साथ काम कर रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर। राज्य में बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के सभी प्रभागों एवं शाखाओं की बारी-बारी से गहन समीक्षा की। इस दौरान अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग व्यवस्था तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति का विस्तार से आकलन किया गया। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी लक्ष्यों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों एवं दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ताकि मरीजों को समय पर बेहतर उपचार मिल सके। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आमजनों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार निरंतर प्रयासरत है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, प्रभावी और जनहितकारी बनें, जिससे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

कचना ओवर-ब्रिज जल्द होगा शुरू

उप मुख्यमंत्री साव ने अंतिम चरण के कार्यों का किया निरीक्षण

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर में खम्हारडीह-कचना रेल्वे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवर-ब्रिज के अंतिम चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को ओवर-ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओवर-ब्रिज पर पैदल चलकर अधिकारियों से इसके तकनीकी मानकों की जानकारी ली। उन्होंने यहां लाइटिंग के लिए अच्छी गुणवत्ता के पोल्स और लाइट्स का उपयोग करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और सेतु संभाग के मुख्य अभियंता श्री एस.के. कोरी भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कचना ओवर-ब्रिज के निरीक्षण के बाद कहा कि इसका 96 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। थोड़े से बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस ओवर-ब्रिज के चालू होने से रायपुर शहर और आसपास के गांवों के हजारों लोगों को ट्रैफिक-जॉम और रेलवे फाटक के बंद होने के कारण यातायात बाधित होने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। श्री साव ने कहा कि राज्य शासन लगातार राजधानी के यातायात को सुदृढ़, व्यवस्थित और तेज करने में लगी हुई है। कचना का यह ओवर-ब्रिज भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है, जो अब लगभग पूर्णता की ओर है। इस सड़क से आना-जाना करने वालों के लिए यह बहुप्रतीक्षित ओवर-ब्रिज जल्द ही खोल दिया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर-वाल्टेयर रेलवे लाइन पर खम्हारडीह और कचना के बीच करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन इस रेलवे ओवर-ब्रिज का 96 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। पुल के मध्य के रेलवे वाले भाग के साथ ही दोनों छोरों पर पुल एवं पहुंच मार्ग का काम पूर्ण कर लिया गया है। अभी पेंटिंग एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। इनके पूर्ण होते ही नाली निर्माण और लाइटिंग का काम तत्परता से प्रारंभ किया जाएगा। इस ओवर-ब्रिज के शुरू हो जाने से इस रूट का यातायात व्यवस्थित और तेज होगा।

कृषि विश्वविद्यालय का ग्यारहवां दीक्षांत समारोह आज

रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का ग्यारहवां दीक्षांत समारोह कल दिनांक 15 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय रायपुर स्थित कृषि मंडपम में प्रात: 11 बजे से आयोजित इस दीक्षांत समारोह में 1 हजार 880 विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व निर्देशक डॉ. अशोक कुमार सिंह दीक्षांत भाषण देंगे। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विद्यार्थियों को दीक्षोपदेश देंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत एवं 2 कांस्य पदक प्रदान किये जाएंगे। इस दौरान भव्य दीक्षांत शोभायात्रा भी निकाली जाएगी।

ग्यारहवें दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कृषि विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियाँ वितरित की जाएँगी। स्नातक कृषि पाठ्यक्रम के 1234 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएँगी। स्नातकोत्तर स्तर पर 518 एवं पी.एचडी. स्तर पर 128 पंजीकृत विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अकादमिक परिधान निर्धारित किया गया है। छात्र कोसे रंग अथवा ऑफ वाईट रंग का कुर्ता तथा सफेद पायजामा पहनेंगे, वहीं छात्राएं कोसे रंग या ऑफ वाईट रंग की साड़ी पहनेंगी।

शिक्षा मंत्री ने यादव विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आज दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलगांव और उरला स्थित शासकीय हाईस्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की संकल्पबद्धता दोहराई।

मंत्री श्री यादव ने बताया कि शैक्षणिक अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत पुलगांव हाईस्कूल यहाँ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 10 नए अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार उरला हाईस्कूल यहाँ अतिरिक्त कक्षों के साथ-साथ एक भव्य हॉल और आधुनिक शौचालय का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से स्कूल में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा और विद्यार्थियों को एक बेहतर अध्ययन वातावरण मिलेगा। सरकार का लक्ष्य हर स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है। विद्यालयों में नए कक्षों के निर्माण से जहाँ छात्रों को सुगम शिक्षण व्यवस्था मिलेगी, वहीं शिक्षकों को भी अध्यापन कार्य में सुगमता होगी। उन्होंने जानकारी दी कि दुर्ग क्षेत्र के अन्य शासकीय स्कूलों में भी संधारण और मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

धान के समर्थन मूल्य में 72 रु. वृद्धि अपर्याप्तः दीपक बैज

रायपुर। केंद्र सरकार के द्वारा तय समर्थन मूल्य में मात्र 72 रू. की वृद्धि अपर्याप्त है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले साल धान के एमएसपी में भी मात्र 69 रु. वृद्धि हुई थी, इस वर्ष जो बढ़ोतरी हुई है वह वर्तमान मूल्य में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जबकि महंगाई वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने और सी 2 फार्मूले से लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने एक

बार फिर किसानों को धोखा दिया है। इस बार खरीफ़ सीजन 2026-27 के लिए मंजूर किए गए एमएसपी की घोषणा के अनुसार धान पर कुल वृद्धि 3 प्रतिशत मात्र है। सी 2 फार्मूले के अनुसार कृषि लागत में नकदी खर्च, खाद, बीज, पानी, रसायन, मजदूरी के साथ ही गैर नकदी लागत के अलावा जमीन की लीज रेंट और उससे जुड़ी खर्च पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाना चाहिए, साथ-साथ किसान परिवार के मेहनत के अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भावनापूर्वक लागत में इनमें से कई खर्चों को शामिल नहीं किया गया। हाल ही में विगत 10 फरवरी 2026 से केंद्र की मोदी सरकार ने पोटाश की कीमत में 15 प्रतिशत और एनपीके की कीमत में 30 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि की है।

सीएम, मंत्रियों के काफिले में कटौती केवल खानापूर्ति : शुक्ला

रायपुर। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के काफिले में कटौती की घोषणा केवल कागजी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज भी मंत्रियो के काफिले में अघोषित रूप से आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां चल रही है। कार्केंड में कटौती का दावा कागजी है, असलियत यही है कि लाव लश्कर में कोई कमी नही है। घोषित गाड़ी के अलावा पायलेट, फॉलो चलाया जा रहा, साथ ही निजी स्टाफ एवं समर्थकों की गाड़ियां

अलग से चल रही है। काफिले की सभी गाड़ियो को जोड़ा जाये तो दो दर्जन से अधिक गाड़ियां एक काफिले में चल रही है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले में भी घोषित रूप से 8 वाहन चल रहे है। विधानसभा अध्यक्ष के काफिले में भी 8 से अधिक वाहन चल रहे है। राजभवन का काफिला भी भारी भरकम है। जबकि अघोषित रूप से इन सबके काफिले में भी अघोषित तौर पर दर्जनों वाहन चल रहे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज भी सरकार के दो दर्जनों से अधिक अधिकारी विभिन्न विभागों के एमडी आदि के घरो में आधा दर्जनों से अधिक वाहन खड़े है। साहब के परिजन उसमें चलते है।

8 जून से 65 ट्रेन रद्द करने निर्णय को वापस ले : ठाकुर

रायपुर। रेलवे प्रशासन को 8 जून से 19 जून तक 65 एक्सप्रेस एवं पेसेंजर ट्रेनो को रद्द करने के निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रेलवे प्रशासन ने 8 जून से 19 जून तक 65 एक्सप्रेस एवं 12 पेसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है वो वर्तमान समय मे उतपन्न पेट्रोल डीजल संकट में घी डालने का काम करेगा।ट्रेन रद्द

होने का सीधा सीधा असर रोजमर्रा के काम काज, छात्र, किसान, मजदूरों, शासकीय कर्मचारियों फेक्ट्री कर्मचारियों पर पड़ेगा जो रोज निजी वाहन एवं ट्रेन से रोज आना जाना करते है एक तो पेट्रोल डीजल संकट चल रहा है उससे आम जनता तनाव में है ऐसे में ट्रेन रद्द होने से उनकी परेशानी बढ़ेगी। 65 एक्सप्रेस एवं 12 पेसेंजर ट्रेनों को रद्द करना जनता के साथ कुठाराघात है एक्सप्रेस रद्द होने से प्रदेश से महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात सहित 10 राज्यों के लिए लोगो को ट्रेन नही मिलेगा। 12 पेसेंजर ट्रेन से रद्द होने से स्थानीय आवागमन भी प्रभावित होगा। रेलवे प्रशासन ऐसे विपरीत समय मे ट्रेन की फेरे बढ़ाये, ट्रेनों की बोगी की संख्या बढ़ाये ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा यात्रा के लिए ट्रेन का उपयोग करे ताकि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो।

भाजपा में अपमानित करने की परंपरा चल रही : वर्मा

रायपुर। भाजपा के कोर कमेटी पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि बदलाव के बहाने अपने ही वरिष्ठ नेताओं को कोर ग्रुप से बाहर करना भाजपा के अंदरूनी संघर्ष को उजागर करता है। नए दौर के अधिनायकवादी भाजपा में जिस तरह से केंद्र की सरकार और भाजपा के केंद्रीय संगठन में हम दो और हमारे दो का कब्जा है उसी तर्ज़ पर छत्तीसगढ़

में भी सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री दोनों उपमुख्यमंत्री और ओपी चौधरी इन्हीं चार लोगों के हाथों में भाजपा संगठन को भी ठेके पर सौंप दिया गया है। किसी भी संगठन में कोर कमेटी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का संगठन होता है जो पार्टी को नीतिगत निर्णय लेने सुझाव देते हैं, सत्ता और संगठन में समन्वय बनाकर जनता और कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर काम करता है लेकिन वर्तमान दौर में भाजपा संगठन नहीं, बल्कि सरकार के नियंत्रण में वसूली गिरोह के तौर पर संचालित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। कैडर और देवतुल्य कार्यकर्ता का दावा केवल जुमला है असलियत यही है कि भाजपा अपने ही नेता कार्यकर्ताओं का शोषण करने वाली पार्टी है। भाजपा के नव गठित कोर कमेटी से भाजपा के सामाजिक न्याय विरोधी चरित्र एकबार फिर उजागर हुआ है।

नाकाम मोदी ने फिर जनता को लाइन में लगा दियाः देवलाल

रायपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने छत्तीसगढ़ और देश में पेट्रोल डीजल गैस की किल्लत पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि देश में पेट्रोल-डीजल, गैस का संकट केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आया है। पहले नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर बैंक के सामने देश की जनता को लाइन में लगाया और पेट्रोल डीजल गैस के लिए।आज छत्तीसगढ़ के कई शहरों

में पेट्रोल-डीजल के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, धमतरी और महासमुंद जैसे जिलों में कई पेट्रोल पंपों पर नो पेट्रोल-नो डीजल बोर्ड लगाए गए हैं। बिलासपुर में कई पंप पूरी तरह ड्राई हो गए हैं और रायपुर में भी कुछ पंप अस्थायी रूप से बंद बताए गए हैं। बिलासपुर में 13 पेट्रोल पंप पूरी तरह खाली हो चुके हैं और बिलासपुर कलेक्टर द्वारा कमर्शियल उपयोग के लिए पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है।आज छत्तीसगढ़ के कई शहरों और कस्बों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। लोग घंटों इंतजार कर ईंधन भरवा रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।परिवहन, व्यापार और रोजमर्रा के कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। जनता में नाराजगी बढ़ रही है।

संवेदनशील शासन, त्वरित समाधान

सुशासन तिहारः जन-विश्वास का नया अध्याय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार अब केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि जन-सरोकारों से जुड़ा एक सशक्त जन-आंदोलन बन चुका है। इस अभियान ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास की एक नई और अटूट कड़ी स्थापित की है। सुदूर वनांचलों से लेकर नगरीय निकायों तक, सरकार स्वयं जनता के द्वार पहुँचकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर रही है।

जनता के द्वार पहुंची सरकार: सुशासन तिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर काटने की विवशता से मुक्ति दिलाई है। प्रशासन स्वयं गांव-गांव पहुँचकर शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के आवेदन सीधे स्वीकार कर रहा है। इन समाधान शिविरों में बड़ी संख्या में मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है, जो साय सरकार की अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है।

त्वरित निर्णय और प्रभावी क्रियान्वयन: शिविरों के दौरान प्रशासनिक संवेदनशीलता का अनूठा स्वरूप देखने को मिल रहा है। पेयजल संकट के समाधान हेतु तत्काल नए हैंडपंपों की स्वीकृति हो या अतिरिक्त राशन दुकान, सड़क, बिजली और आवास से जुड़े मामले, निर्णय मौके पर ही लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि जन-समस्याओं का समाधान समय-सीमा के भीतर हो। इसी के अनुरूप जिला प्रशासनों को जवाबदेह बनाते हुए अधिकारियों को पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिल रहा सीधा लाभ: राज्य सरकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु समाज का वंचित वर्ग है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हजारों परिवारों को पक्की छत मिल रही है। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। किसानों को सम्मान निधि, आधुनिक उपकरण और सिंचाई सुविधाओं का लाभ निरंतर मिल रहा है। शिविरों में आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान किताब और जॉब कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेजों का तत्काल वितरण सरकार की क्रियान्वयन शक्ति को दर्शाता है।

प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा संदेश दिया है कि जन-समस्याओं के प्रति लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे जनता से संवाद कर समस्याओं का फीडबैक लेना प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित के प्रति उनकी गंभीरता को रेखांकित करता है, जिससे नागरिकों में शासन के प्रति गहरा भरोसा जगा है।

जनभागीदारी से सुदृढ़ होता लोकतंत्र: इस अभियान ने शासन व्यवस्था को अधिक सहभागी और जन-केंद्रित बनाया है। जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने सुशासन तिहार को लोकतंत्र के वास्तविक उत्सव में बदल दिया है। यह पहल केवल शिकायतों के निवारण तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का माध्यम बन रही है

नए छत्तीसगढ़ की आधारशिला: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। सुशासन तिहार इसी विजन का मूर्त रूप है। आज जब गांवों में समय पर समस्याओं का समाधान और योजनाओं का पारदर्शी लाभ मिल रहा है, तो यह विश्वास और भी प्रबल हो रहा है कि छत्तीसगढ़ तेजी से सुशासन और जनकल्याण के एक स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे संकल्पों की सिद्धि का एक महापर्व है। हमारी सरकार का मूल मंत्र है- ''जनता की सेवा ही सर्वोच्च प्राथमिकता'' । विगत कुछ समय से आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में जिस तरह आप सभी की सक्रिय भागीदारी दिख रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि अब शासन और जनता के बीच की दूरियां मिट चुकी हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अब आपको अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं आपके द्वार खड़ा हो।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.